04 - अखिलेश को 'आंखें' दिखाने का राज

05 - केवल दक्षिण अफ्रीका नहीं, पूरी मानवता के साझा नायक

A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 18 जुलाई, 2026

06 - एमपी में मोबाइल गवर्नेंस एवं विकास विषय पर पुस्तक...

07 - संरक्षित खेती एवं जल संरक्षण में आधुनिक तकनीकों...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 11 अंक 285, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारत-यूके फ्री टैरिफ का सर्वाधिक लाभ कृषि निर्यात को

केशव पद्मनाभन

एक ब्रिटिश अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारत-यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच भरोसे का 'फ्लोर' है और इससे उन्हें आगे चलकर ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा, जिसमें वॉन्टेड भगोड़ों का एक्सट्रैडिशन और सिक्योरिटी को-ऑपरेशन के दूसरे एरिया शामिल हैं।

नई दिल्ली और लंदन के बीच पिछले साल साइन किया गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) 15 जुलाई, 2026 को लागू हुआ। यह G7 देश के साथ भारत का पहला बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो ऑपरेशनल होगा। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने की 'भावना और टोन को दिखाने में मदद करता है', जिससे दूसरे मुद्दों पर ज़्यादा खुलकर चर्चा हो सकेगी। अधिकारी ने आगे कहा कि यह 'भारत के साथ हाई लेवल के भरोसे' को दिखाता है, खासकर तब जब नई दिल्ली की इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है।

CETA पर बातचीत 2022 में शुरू हुई थी और 14 राउंड के बाद, आखिरकार पिछले साल साइन हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके गए थे। 30 चैप्टर वाले इस एग्रीमेंट में यूके को होने वाले 99 परसेंट इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम या खत्म करने का प्रावधान है, जबकि नई दिल्ली ब्रिटिश इंपोर्ट पर लगभग 90 परसेंट ड्यूटी को आसान बनाएगी या खत्म करेगी। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को ट्रेड डील पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, 'यह ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है।' यह डील भारत की बदलती ट्रेड पॉलिसी का एक अहम संकेत है।

2019 में, नई दिल्ली मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट–रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर हो गई थी, जिसमें भारत को छोड़कर एशिया-पैसिफिक रीजन की 15 सबसे बड़ी इकॉनमी शामिल हैं। भारत का सबसे बड़े मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट से पीछे हटना ऐसी डील से कथित तौर पर पीछे हटने जैसा था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के बाद, भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ CETA सहित कई देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू की।

ब्रिटिश के लिए, इस डील से स्कॉच व्हिस्की और प्रीमियम ऑटोमोबाइल सहित उसके मुख्य एक्सपोर्ट के लिए कई फायदे होने वाले हैं। भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस डील में सर्विसेज़ और सरकारी खरीद पर चैप्टर शामिल हैं, जिससे यह बहुत बड़ा हो गया है। इस ट्रेड डील से कई सेक्टर्स को बड़े फायदे होंगे, स्कॉच पर इंपोर्ट ड्यूटी 150 परसेंट से घटाकर 75 परसेंट कर दी गई है...प्रीमियम यूके कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110 परसेंट से घटकर 10 परसेंट हो जाएगी। रिटेल सेक्टर में यूके के सबसे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स और स्पोर्ट्स के सामान भारतीय कंज्यूमर्स के लिए सस्ते में खरीदे जा सकेंगे।'

'ब्रिटिश दूत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यूके में बने टर्बाइन, जनरेटर और दूसरे कंपोनेंट्स भी भारतीय कंपनियों के लिए सस्ते में खरीदे जा सकेंगे। इस डील से यूके कंपनियों के लिए भारतीय खरीद मार्केट में बोली लगाना आसान हो जाएगा। भारतीय खरीद मार्केट सालाना 38 बिलियन पाउंड का है।'

डील पूरी होने के बाद भी, दोनों देशों ने दो बड़े सेंसिटिव मुद्दों, डबल कंट्रीब्यूशन्स कॉन्ट्रावेंशन एग्रीमेंट (DCC) और स्टील पर बातचीत जारी रखी। मई 2025 में डील के फाइनल होने की ओरिजिनल घोषणा में यह बताया गया था कि यूके में टेम्पररी तौर पर काम करने वाले भारतीय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को 39 महीने तक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। इसे बाद में बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया।

यूनाइटेड किंगडम में टेम्पररी तौर पर काम करने वाले भारतीय एम्प्लॉई को ब्रिटिश सोशल सिक्योरिटी सर्विस में अपनी सैलरी का लगभग 25 परसेंट नहीं मिलेगा, खासकर अगर वे अपने असाइनमेंट के बाद घर लौटते हैं.

कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल के अनुसार, इसे भारतीय सर्विस सेक्टर के लिए 'गेम चेंजर' माना जा रहा है। हालांकि, इस एग्रीमेंट में ब्रिटिश कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। एक ब्रिटिश अधिकारी ने CBAM का बचाव करते हुए कहा कि लंदन इस मैकेनिज्म को 'ट्रेड इशू' के तौर पर नहीं देखता, बल्कि रिसोर्स हैवी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन की कॉस्ट को 'इकॉनॉमिक्स' करने के लिए यूके के लिए ज़रूरी मानता है।

इस एग्रीमेंट से उम्मीद है कि भारतीय किसानों और सीफ़ूड प्रोड्यूसर को यूके को अपने एक्सपोर्ट के लिए कॉम्पिटिटिव फ़ायदा मिलेगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चरल मार्केट की कीमत लगभग 90 बिलियन है। भारतीय सीफूड प्रोड्यूसर को 15 जुलाई 2026 से यूके को अपने एक्सपोर्ट के लिए पूरी टैरिफ छूट मिलेगी। यह एग्रीमेंट भारत के अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे डेयरी, अनाज और दालों की सुरक्षा करता है, साथ ही सोने और ज्वेलरी और स्मार्टफोन जैसे दूसरे सेक्टर की भी सुरक्षा करता है। दोनों देशों के बीच मौजूदा बाइलेटरल ट्रेड लगभग 48 बिलियन पाउंड या 60 बिलियन डॉलर का है।

ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस ट्रेड एग्रीमेंट से बाइलेटरल ट्रेड में हर साल लगभग $ 34 बिलियन की बढ़ोतरी होगी, जबकि भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में हर साल लगभग $ 6.83 बिलियन की बढ़ोतरी होगी। अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के कुछ हिस्सों को खोलने के बावजूद, यूके ने चिकन, पोर्क, अंडे, चावल और चीनी जैसे सामानों में कोई रियायत नहीं दी है। यूके द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट पर लगाए गए दूसरे टैरिफ, जैसे प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स पर 70 परसेंट, इंजीनियरिंग गुड्स पर 18 परसेंट तक, लेदर और फुटवियर प्रोडक्ट्स पर 16 परसेंट तक, और टेक्सटाइल और कपड़ों पर 12 परसेंट तक, सभी को लंदन ने खत्म कर दिया है।

इन गुड्स के इम्पोर्ट के लिए एक नया कोटा शुरू होने के साथ, ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर टैरिफ मौजूदा 110 परसेंट से घटकर लगभग 10 परसेंट रह जाएगा। 2036 तक, ब्रिटिश गुड्स पर भारतीय टैरिफ का लगभग 85 परसेंट ज़ीरो हो जाएगा। स्टील के मामले में, भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूके के 1 जुलाई को शुरू किए गए उपायों के खिलाफ़ कुछ सुरक्षा मिलती है। यह सुरक्षा एक देश के खास कोटा, बचे हुए कोटा और ऑथराइज़्ड यूज़ स्कीम (AUS) के ज़रिए है, जिससे लगभग 85 परसेंट भारतीय स्टील एक्सपोर्ट को नए ब्रिटिश उपायों से बाहर रखा जा सकता है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने स्टील पर उपायों का बचाव करते हुए कहा कि यह उनकी अपनी 'नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस' में 'पूरी तरह से योगदान देता है।' दोनों देश बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए। CETA और DCC पर एक साथ बातचीत हुई। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी बातचीत का हिस्सा थी, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुई है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

जींद से रवाना हुई देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

जींद (एजेंसी)। भारतीय रेलवे शुक्रवार को हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का संचालन शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह परियोजना केवल एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के ऊर्जा परिवर्तन की नई पहचान है, जहां डीजल आधारित परिवहन से आगे बढ़ते हुए स्वच्छ, टिकाऊ और भविष्य की ऊर्जा तकनीक को अपनाया जा रहा है। बता दें कि जर्मनी व्यावसायिक हाइड्रोजन यात्री ट्रेनों को शुरू करने वाला पहला देश बन चुका है, जबकि फ्रांस, इटली, चीन और जापान प्रायोगिक परियोजनाओं या सीमित परिचालन पर काम कर रहे हैं। इन देशों की ट्रेनों में आमतौर पर दो से चार डिब्बे होते हैं और ये क्षेत्रीय सेवाएं देती हैं।

- **धुएं की जगह छोड़ेगी सिर्फ पानी, खुद बनाएगी अपनी बिजली**

पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं

वहीं, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच है, जिसमें 2600 यात्री एक साथ सवारी कर सकेंगे। अगले चरण में 34 और हाइड्रोजन ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों में दौड़ती दिखाई देंगी। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित की गई है तथा स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। हाइड्रोजन से बिजली उत्पन्न कर यह ट्रेन चलाई जाएगी। धुएं की जगह केवल जलवाष्प निकलेंगे, जिससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी। 3200 हार्सपावर के साथ यह नमो भारत हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष की मौजूदगी में हरियाणा के विकास से जुड़ी करीब 15 हजार करोड़ की आठ परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया।

मानसून सत्र 20 जुलाई से सरकार 7 बिल लाएगी

- **वंदे मातरम् के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी**

नई दिल्ली (एजेंसी)। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई 20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। यह सत्र 25 दिनों तक चलेगा, कुल 19 बैठकें होंगी। दिल्ली के कर्तव्य भवन में शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और ललन सिंह समेत कई सीनियर लीडर शामिल हुए। सात में से दो विधेयक फॉरेन कंट्रीब्यूशन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़ा विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर 2025 को पेश किया गया था।

इन पांच जिलों में कुल ढाई लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा

स्लीमनाबाद टनल पांच जिलों के लिए बनेगी अमृतधारा : सीएम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र हर प्रकार के संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी की कमी की चुनौती सामने आती है। स्लीमनाबाद टनल कटनी, रीवा, सतना, मैहर और पन्ना जिलों के लिए अमृतधारा बनेगी। भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से चित्रकूट क्षेत्र और विंध्य की वैली के इन पांच जिलों के कुल ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। लोगों के लिए पेयजल की समस्या का समाधान होगा।

- **1600 करोड़ से अधिक की राशि से बनी 12 किमी टनल परियोजना**

कई स्थानों पर इसमें बिजली भी बनाई जाएगी। यह परियोजना राज्य में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के संकल्प की पूर्ति में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों की ओर से टनल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि में केंद्र सरकार ने लगभग 275 करोड़ की राशि प्रदान की। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बलबूते आज यह चुनौतीपूर्ण टनल परियोजना पूरी होने की ओर बढ़ रही है। किसानों और क्षेत्र के व्यापारियों के लिए यह टनल एक वरदान की तरह है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भविष्य में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केस स्टडी सिद्ध होगी।

मां नर्मदा, गंगा बेसिन में भी हरियाली लाएंगी

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नर्मदा नदी तो खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन यह विज्ञान का चमत्कार ही है कि अब मां नर्मदा इस ऐतिहासिक टनल के माध्यम से गंगा बेसिन में सोन नदी के आसपास के अंचल में भी हरियाली लाएगी। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि टनल तैयार होना असंभव जैसा है। लेकिन जब संकल्प बड़ा होता है और पवित्र मन से कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बार-बार कठिन चट्टानों की चुनौतियां आने के बावजूद नर्मदा टनल को पूरा करने के संकल्प के साथ पूरी टीम काम करती रही। राज्य में एक समय पर सिंचाई का रकबा केवल साढ़े 7 लाख हेक्टेयर था। हमारी सरकारों में यह रकबा बढ़ाकर 44 लाख हेक्टेयर हुआ, जो पिछले ढाई साल में बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसान कल्याण वर्ष में नर्मदा टनल परियोजना किसानों के लिए बड़ी सौगात है। आगामी तीन माह में रबी की फसल के लिए किसानों को एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा।

इंजीनियर-टेक्निशियन और मजदूर, सफलता के लिए संघर्ष करते रहे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 8 घंटे की तीन शिफ्ट में टनल बनाने के लिए काम शुरू किया गया। वर्ष 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन वर्ष 2016 से टनल के अपस्ट्रीम छोर से जर्मनी से लाई गई आधुनिक मशीन से खुदाई की गई। इसके बाद चुनौतियां बढ़ती चली गई, लेकिन इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य में लगे रहे। टनल निर्माण के लिए लंबा संघर्ष रहा है और अब वर्ष 2026 में सफलता मिली है। टनल तैयार होने के बाद अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगभग ढाई लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। प्रेस से संवाद के समय नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, विधायक श्री संदीप जायसवाल, श्री संजय पाठक तथा अधिकारी गण उपस्थित थे।

सुप्रभात

तुम्हारी स्मृति
फूल-सी
मेरे दिल में
महकती रहती है

तुम्हारी स्मृति
नदी-सी
मेरे अंदर
बहती रहती है

तुम्हारी स्मृति
मेरी साँसों को
साँस देती रहती है

तुम्हारी स्मृति
मेरे जीवन को
युवा बनाये रखती है

तुम्हारी स्मृति
मेरे समय को
अलंकृत करती रहती है।

– दुर्गाप्रसाद झाला

पुरी रथयात्रा : तीनों रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचे

- **अब तीनों देवता 9 दिन मौसी के घर रहेंगे**
- **दूसरे दिन भी भारी भीड़, नौ लाख श्रद्धालु जुटे**

पुरी (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ शुक्रवार दोपहर गुंडिचा मंदिर पहुंच गए। अब तीनों देवता 9 दिन अपनी मौसी के घर रहेंगे। इसके साथ ही रथयात्रा पूरी हुई। इसके पहले रथयात्रा शुक्रवार सुबह दूसरे दिन शुरू हुई। बह बारिश और उमस के बीच 9 लाख श्रद्धालु फिर से रथ खींचने के लिए ग्रैंड रोड पर जुटे। गुरुवार को पाहंडी अनुष्ठान में हुई देरी और अंधेरा होने के कारण तीनों रथ गुंडिचा मंदिर तक नहीं पहुंच सके थे। तीनों देवता रातभर अपने-अपने रथों पर ही विराजमान रहे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने बताया कि सभी अनुष्ठान समय पर हुए, लेकिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा मुख्य द्वार पर करीब 40 मिनट तक आगे नहीं बढ़ सकी। इसी वजह से पाहंडी अनुष्ठान एक घंटे से अधिक देर से पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि भगवान बलभद्र का तालध्वज रथ ग्रैंड रोड पर करीब 700 मीटर चलकर मार्केट चौक पर रुका। देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ लगभग 400 मीटर चलकर मरीचिकोट चौक तक पहुंचा। वहीं भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ कुछ ही दूरी तय कर मुख्य मंदिर के सिंहद्वार के पास रुक गया था।

- **बारिश के बावजूद नहीं टूटा श्रद्धालुओं का उत्साह–** बारिश और उमस के बावजूद लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ और हरि बोल के जयघोष के बीच रथ खींचते रहे। ग्रैंड रोड पर झांझ, नगाड़ों, शंख और तुरहियों की गूंज के बीच श्रद्धालु नाचते–गाते नजर आए। बारिश का पानी जमा न हो, इसके लिए ग्रैंड रोड पर विशेष इंतजाम किए गए, ताकि रथयात्रा बिना रुकावट आगे बढ़ सके। पाहंडी के दौरान भगवान जगन्नाथ के पारंपरिक फूलों के मुकुट तहिया के नहीं दिखने पर अरविंद पाधी ने जानकारी दी है।

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

मध्य प्रदेश में नया लेबर कोड लाने की तैयारी

नाइट शिफ्ट वालों को रात में 1 घंटे के काम के बदले मिलेगा डेढ़ घंटे का पैसा

भोपाल। मध्य प्रदेश में नाइट शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार अगले हफ्ते विधानसभा में 'एमपी कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेसेज, 2026' विधेयक पेश करने जा रही है। इस नए ड्राफ्ट कोड के तहत अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं, तो आपको दिन में काम करने वाले कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिल सकती है। नए फ्रेमवर्क के मुताबिक, रात के समय किए गए 1 घंटे के काम को वेतन और काम के घंटों की गणना के लिए दिन के डेढ़ घंटे के बराबर माना जा सकता है।

जापान के मॉडल पर तैयार हुआ नियम

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह अनोखा प्रावधान जापान और अन्य विकसित देशों के नाइट-वर्क मॉडल का अध्ययन करने के बाद शामिल किया गया है। इन देशों में जैविक घड़ी और सामाजिक जीवन में आने वाले व्यवधान को देखते हुए रात में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त मुआवजा या बढ़ा हुआ वेतन दिया जाता है। ड्राफ्ट के मुताबिक, सरकार जल्द ही इस बढ़ी हुई मजदूरी के स्ट्रक्चर और लागू होने की तारीख को नोटिफाई करेगी।

महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मंजूरी

इस नए कानून में महिलाओं के कार्यस्थल को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते नियोक्ता केंद्र सरकार के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड, 2020 के तहत तय सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लिखित सहमति की शर्तों को पूरा करते हों। इसके साथ ही, नए कानून के तहत राज्य में दुकानों, मॉल और दफ्तरों को 24 घंटे यानी सातों दिन चौबीस घंटे संचालित करने की छूट दी जाएगी। हालांकि, सरकार शराब दुकानों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए अलग से काम करने के घंटे तय करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेगी।

विधानसभा उपचुनाव-2026 के मद्देनज़र सघन चेकिंग के दौरान एक दिन में 36.19 लाख रुपये नकद जप्त

भोपाल। विधानसभा उपचुनाव-2026 के दृष्टिगत दतिया जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सतत करवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दतिया श्री मयूर खण्डेलवाल के निर्देशन, में जिलेभर में सघन वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न अंतरजिला एवं प्रमुख चेकिंग पॉइंटों का लगातार निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवढ़ा चुंगी चेकिंग पॉइंट का आकस्मिक भ्रमण किया इसी दौरान एक कार सवार युवक के कब्जे से करीबन रू. 15,00,000 नकद राशि

बरामद की गई। मौके पर एसएसटी को सूचना देकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

इसी क्रम में गोराघाट चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग के दौरान एमपी-09-ZD-9082 स्कॉर्पियो वाहन से रू. 21,19,000 नकद राशि बरामद की गई। वाहन स्वामी से राशि के संबंध में पूछताछ की जा रही है तथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार दतिया पुलिस द्वारा एक ही दिन में कुल रू. 36,19,000 की नकद राशि बरामद कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

दतिया पुलिस द्वारा विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रमुख मार्गों, अंतरजिला सीमाओं एवं संवेदनशील स्थानों पर लगातार सघन वाहन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

पेंशनरों ने दिया सरकार को धन्यवाद

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सतत प्रयासों एवं न्यायालयीन प्रकरण दायर करने के बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धारा 49 के अंतर्गत महंगाई राहत देने से पूर्व लेने वाली सहमति की अनिवार्यता को समाप्त किया गया इसके लिए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दोनों राज्य सरकारों को धन्यवाद दिया है।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा धारा 49 को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की है जिसमें केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य को नोटिस जारी किए गए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय में दिए गए उत्तर में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सहमति लेने की अनिवार्यता के संबंध में कोई जवाब नहीं दे पाई है ।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बकाया 81 महीने के महंगाई राहत के शीघ्र भुगतान की मांग की है एवं यह भी बताया की सहमति का प्रावधान अधिनियम में था ही नहीं इसके बाद भी दोनों राज्य सरकारें पेंशनरों का लगातार 25 वर्षों से शोषण करती आ रही है ।

आप भोले के भक्त, छोटी बातों पर हुड़दंग ना करें

यूपी के शामली में कांवड़ियों से सीएम योगी की अपील

शामली (एजेंसी)। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों से हुड़दंग न करने की अपील की है। शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़िए भगवान राम के वंशज और भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए छोटी–छोटी बातों पर विवाद या हुड़दंग से बचें।

यदि कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करे तो उसे तत्काल अलग कर दें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई हंगामा या अनुशासनहीनता होती है, तो विपक्ष ऐसे दृश्यों पर ध्यान देगा और फिर अतीत की तरह कांवड़ यात्रा को बाधित करने के लिए किसी भी तरह से अन्य स्थानों से दबाव बनाने का प्रयास करेगा। सीएम योगी ने कहा कि जीवन में, धैर्य और अनुशासन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होनी चाहिए।

गमछा, गोली और बांकीपुर उपचुनाव !

बीजेपी के लिए गंभीर खतरा बन गये हैं प्रशांत किशोर !

पटना (एजेंसी)। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का पहले कैंडीडेट बदला। उसके बाद तत्काल राजधानी पटना में बंटी यादव की हत्या का होना। बांकीपुर की गलियों में विकास का नहीं दिखना। ये सारे फैक्टर प्रशांत किशोर के लिए मददगार साबित होने लगे हैं। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सियासी जानकार ऐसा मानते हैं।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जब बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात की, तब कहा कि जब सरकार का मुखिया ही जाति, गमछा और धर्म देखकर गोली मारने की बात करते हैं, तो अपराधियों को मन कैसे नहीं बढ़ेगा। पीके ने कहा कि बंटी यादव के हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सम्राट चौधरी के गमछा, गोली और जाति वाली बात को दोहराया। लोगों से कहा कि मौत के बाद किसी का चरित्र हनन करना सही नहीं है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झिंझरी और बहोरीबंद सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण

विद्यार्थी निजी विद्यालयों से निकलकर शासकीय सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति सभी के प्रति मैत्री और कल्याण का भाव रखने का संदेश देती है। कृष्ण-सुदामा का प्रसंग भी हमें मैत्री के भाव को पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ निभाने का संदेश देता है। यह प्रसंग हमें अमीर-गरीब का भेद मिटाकर समरसता का संदेश भी देता है। भगवान कृष्ण का शिक्षा के लिए सांदीपनि आश्रम उज्जैन आगमन और शिक्षा ग्रहण कर उनका 64 कलाओं 14 विद्याओं में पारंगत होना हमें शिक्षा का महत्व बताता है। राज्य सरकार बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सांदीपनि विद्यालयों की सौगात दे रही हैं। प्रदेश के सांदीपनि विद्यालय सर्वसुविधा युक्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का माध्यम बन रहे है। इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी निजी विद्यालयों से निकलकर शासकीय सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। शासकीय शालाओं में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और साइकिलें प्रदान की जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में टॉप करता है तो उसे स्कूटी दी जा रही है। राज्य में गुरुपूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसीलिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए कुलगुरु संबोधन की परंपरा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्लीमनाबाद कटनी में सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

जगदीशपुर में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश एक देश, एक विधान, एक निशान और एक कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विधानसभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र में प्रदेश में सभी धर्मावलंबियों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लायी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के पास जगदीशपुर स्थित है, इसका नाम विदेशी आक्रांताओं ने बदलकर इस्लामनगर कर दिया था। विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र से पहले जगदीशपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक कर समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रक्षाबंधन से एक बार फिर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1500 रुपए की राशि बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम को सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद श्री गणेश सिंह, विधायक श्री संजय पाठक, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित थे।

एसआईआर में नाम कटने पर सरकारी सुविधाएं देने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इसमें मांग की गई है कि जिन लोगों के

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग और बंगाल सरकार से जवाब मांगा

नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कट गए हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलना बंद नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई से पहले हो सकती है। याचिकाकर्ता प्रसेंजित बोस ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट

जाता है, तो सिर्फ इसी वजह से उसका राशन, अन्नपूर्णा योजना और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद नहीं होना चाहिए। जब तक उसकी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक उसके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए।

चंडीगढ़ में बनेगा नया एमबीबीएस कॉलेज

- पीएम ने 4700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन
- कहा-चंडीगढ़ के विकास से तीन राज्यों को फायदा होता है

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पीजीआई में उन्होंने 10 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का फायदा भी होता है। मैं चंडीगढ़ होता तो खुद भी पीजीआई जाता था। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नए एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही वहां पढ़ाई शुरू होगी। मंच पर चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद रहे। जिन प्रोजेक्टों का पीएम ने उद्घाटन और शिलान्यास किया, उनमें विरोधी दलों के सांसदों का भी नाम लिखा था। जिनमें चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के अलावा श्री आनंदपुर साहिब से एएपी के सांसद मालविंदर कंग शामिल हैं। पीएम ने इसके बाद जालंधर जाकर एक सभा की।

- कंट्रोल टावर को निशाना बनाया, लगातार छठी रात ईरान पर एयरस्ट्राइक की

अमेरिका का भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने शुक्रवार को लगातार छठी रात ईरान पर एयरस्ट्राइक की। इस दौरान भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमले में पोर्ट के कंट्रोल (निगरानी) टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की है। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने चाबहार पोर्ट और कंट्रोल टावर पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। पिछले एक हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया

कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। कमांड ने कहा कि हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने इसके विकास में निवेश किया है और इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है।

- **जॉर्डन में अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया–** ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक, यह हमला अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ जारी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले जॉर्डन की सेना ने कहा था कि उसने देश की ओर दागी गई ईरान की तीन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। शिपिंग डेटा के मुताबिक, गुरुवार को होर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ तीन मालवाहक जहाज गुजरे। यह मई के बाद एक दिन में सबसे कम आवाजाही है। हालिया ईरानी हमलों और ईरान से जुड़े जहाजों पर अमेरिकी नाकाबंदी फिर शुरू होने के बाद ज्यादातर जहाज या तो रुक गए या बीच रास्ते से लौट गए।

सुंदरबन से अब झांक भी नहीं सकेंगे बांग्लादेशी

बीएसएफ ने बॉर्डर पर 90 किमी इलाके में बाड़बंदी की तैयारी की

कोलकाता (एजेंसी)। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा के साथ सुंदरबन के लगभग 90 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने की कवायद शुरू कर दी है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) फेंसिंग के लिए टेक्निकल स्टडी कर रहा है। फिलहाल घने जंगल, मैनग्रूव और दलदली इलाके वाले सुंदरबन में फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट से निगरानी कर रही है। बीएसएफ के लिए बाड़बंदी मुश्किल टास्क है, क्योंकि भोगौलिक तौर से इस इलाके में किसी तरह का निर्माण आसान नहीं है।

12 फुट ऊंची फेंसिंग की जा रही है

बीएसएफ के मुताबिक, सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए और सर्चलाइट, सर्विलांस कैमरे और समुद्री गश्त को बढ़ाया जाएगा। जिन इलाकों में बाड़बंदी पूरी हो गई है, उसमें सर्विलांस कैमरे लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 फुट ऊंची फेंसिंग ऐसी है, जिसे पार करना संभव नहीं है। बांग्लादेश से लगे इलाकों में कंट्रोल रूम की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि घुसपैठियों पर नजर रखी जा सके।

- **174 किमी पर बाड़ लगाना संभव नहीं–** बंगाल सरकार से जमीन मिलने के बाद सरहद पर जमीन की पैमाइश की है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन बीएसएफ को सौंप चुकी है। दिनाजपुर , दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, नादिया, कूच बिहार में 175 किमी बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किमी लंबी है। अभी तक सिर्फ 79 प्रतिशत बॉर्डर इलाके में बाड़बंदी हुई है।

जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा देने की तैयारी

बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने 11–14 जुलाई को सुंदरबन का दौरा किया और बाड़बंदी के काम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सुंदरबन में फेंसिंग के तौर–तरीकों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सामने आया कि भोगौलिक चुनौतियों के अलावा स्थानीय लोग भी जमी अधिग्रहण से डर रहे हैं। इलाके में चल रहे कई मध्यम–स्तर के होटलों और लॉज ने भी चिंता जताई है कि उन्हें जगह बदलने के लिए कहा जा सकता है। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय लोगों को समझाया गया है कि बाड़ लगाना जरूरी है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है और सुरक्षा विभाग जल्द ही फेंसिंग शुरू करेगा। लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें मुआवज़ा और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी।

एमवाय अस्पताल में 9 मंजिला नए भवन का निर्माण, 800 करोड़ से विस्तार होगा

1600 बिस्तरों, 40 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित होगा अस्पताल

इंदौर। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सा संस्थानों में शामिल महाराजा यशवंतराव (एमवाय) चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत 9 मंजिला नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला यह सर्वसुविधायुक्त अस्पताल न केवल इंदौर बल्कि पूरे मालवा-निमाड़ अंचल के मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। गुरुवार को संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी और बड़ी संख्या में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि नया अस्पताल भवन तीन खंडों ए, बी और सी में विकसित किया जा रहा है। फिलहाल सी खंड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस हिस्से में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर सहित कई महत्वपूर्ण चिकित्सा विभाग स्थापित किए जाएंगे। पूरे अस्पताल परिसर में कुल 40 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे, जिससे जटिल शल्य चिकित्सा सेवाओं की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

निर्माण चिकित्सा मानकों के अनुरूप

उन्होंने बताया कि नए अस्पताल में कुल 1600 बिस्तरों की व्यवस्था रहेगी। ए खंड में प्रशासनिक कार्यालय और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) संचालित होंगे, जबकि अन्य दोनों खंडों में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा विभाग विकसित किए जाएंगे। भवन का निर्माण आधुनिक चिकित्सा मानकों के अनुरूप किया जा रहा है, ताकि मरीजों को एक ही परिसर में उच्च स्तरीय उपचार की सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने किया था भूमि पूजन - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 दिसंबर 2025 को एमवाय चिकित्सालय परिसर में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि-पूजन किया था। मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के माध्यम से निर्मित किए जा रहे इस अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, अस्थि रोग, शिशु रोग, शिशु शल्य चिकित्सा, न्यूरो सर्जरी, नाक-कान-गला रोग, दंत रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, मातृ एवं शिशु वार्ड तथा आपातकालीन चिकित्सा सहित अनेक सुपर स्पेशियलिटी विभाग विकसित किए जाएंगे। नया अस्पताल भवन तैयार होने के बाद एमवाय चिकित्सालय की उपचार क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। अत्याधुनिक संसाधनों और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित यह परियोजना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

ट्रेन में खोया मंगलसूत्र स्टाफ की तत्परता से मिला, यात्री को सौंपा

टीटीई गोपाल लाल मीणा को कोच में खोया मंगलसूत्र मिला

इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में रेलवे सुरक्षा बल एवं ऑन-ड्यूटी टिकट चेकिंग स्टाफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से शांति एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान खोया सोने का मंगलसूत्र सुरक्षित बरामद कर उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दिया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 19310 शांति एक्सप्रेस से देवास से रतलाम की यात्रा कर रहे श्री लक्ष्य ताम्रकार ने रेल मदद के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई कि यात्रा के दौरान उनकी पत्नी का सोने का मंगलसूत्र कहीं गिर गया है अथवा चोरी हो गया है। शिकायत प्राप्त होते ही रेलवे सुरक्षा बल ने बिना विलंब कार्रवाई प्रारंभ की। रतलाम आरपीएफ पोस्ट के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह तोमर ने

शिकायतकर्ता से संपर्क कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आरपीएफ कंट्रोल के माध्यम से संबंधित ट्रेन के ऑन-ड्यूटी टिकट चेकिंग स्टाफ को तत्काल सूचना देकर संबंधित कोच की गहन जांच कराई गई तथा अगले स्टेशन पर विशेष रूप से कोच की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए। ट्रेन के मेघनगर स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र पाल ने ट्रेन को अटेंड किया। इस दौरान ऑन-ड्यूटी टीटीई गोपाल लाल मीणा को कोच में मिला सोने का मंगलसूत्र आरपीएफ को सौंपा गया। इसके बाद शिकायतकर्ता से संपर्क कर उन्हें मंगलसूत्र सुरक्षित मिलने की जानकारी दी गई तथा नियमानुसार उसे वापस करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

16 जुलाई 2026 को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद रेलवे सुरक्षा बल, मेघनगर द्वारा लगभग तीन लाख रुपये मूल्य का सोने का मंगलसूत्र लक्ष्य ताम्रकार को सुरक्षित लौटा दिया गया। अपना बहुमूल्य आभूषण वापस मिलने पर यात्री एवं उनके परिजनों ने रेलवे सुरक्षा बल तथा टिकट चेकिंग स्टाफ की त्वरित कार्रवाई, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

सफाई कर्मचारियों का आंदोलन

इंदौर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। वाल्मीकि सेना के बैनर तले सफाई कर्मचारी शुक्रवार 17 जुलाई से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेश गौहर ने कहा कि वर्षों से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, समय पर वेतन का भुगतान हो, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिले तथा सफाई कार्य के दौरान दस्ताने, मास्क, जूते सहित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर बेहतर इलाज और बीमा योजना लागू करने तथा कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई। महेश गौहर ने बताया कि आंदोलन केवल इंदौर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेशभर के नगर निगमों और नगरीय निकायों में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी एक साथ धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की अपील भी की गई है।

डॉक्टर के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ठगी

इंदौर। शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने उनके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करते हुए अमेजन से 37 हजार के गिफ्ट वाउचर खरीद लिए। मोबाइल पर लेनदेन का संदेश मिलने के बाद डॉक्टर को ठगी का पता चला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार निजी अस्पताल में कार्यरत डॉ. दीपक पाटीदार 7 जून को विजयनगर क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से रू. 37 हजार की खरीदारी का बिल प्राप्त हुआ। संदेश देखकर उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने लेनदेन की जानकारी की जांच की। जांच में सामने आया कि उनके क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर अमेजन के गिफ्ट वाउचर खरीदे गए हैं। ठगी की जानकारी मिलते ही डॉ. पाटीदार ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामला विजयनगर थाना पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्ड की जानकारी किस माध्यम से अपराधियों तक पहुंची तथा रकम का उपयोग किस प्रकार किया गया।

कपड़ा व्यापारी पर हथियार से हमला

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक कपड़ा व्यापारी पर बीच-बचाव करने की रंजिश में हमला कर दिया गया। आरोप है कि दिन में दुकान के बाहर हुए विवाद को शांत कराने से नाराज बदमाशों ने रात में घर लौटते समय व्यापारी को रेलवे अंडरब्रिज के पास घेर लिया और मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसूड़िया थाना पुलिस के अनुसार गौरी नगर निवासी शुभम यादव की शिकायत पर विनय और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट तथा धारदार हथियार से हमला करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। शुभम ने पुलिस को बताया कि उसकी सिंगापुर टाउनशिप में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। शिकायत के मुताबिक बुधवार शाम दुकान के बाहर विनय और उसके साथी कुछ युवकों से विवाद कर रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख शुभम ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर मामला शांत करा दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने रात में घर लौटते समय रेलवे अंडरब्रिज के पास उसे रोक लिया और हमला कर दिया। घटना में घायल शुभम को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महिला महा दंगल, जिम्मेदारी महिलाओं को

इंदौर। शहर में पहली बार 18 और 19 जुलाई को खंडवा रोड स्थित लिंबोदी के गंगा गार्डन में दो दिवसीय 'मध्य प्रदेश महिला योद्धा कुश्ती' महा दंगल आयोजित होगा। इसकी खास बात यह है कि प्रतियोगिता में केवल महिला पहलवान ही नहीं, बल्कि संचालन, रेफरी, तकनीकी व्यवस्था और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में होगी। आयोजन समिति की अध्यक्ष स्वाति काशिद ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 300 से अधिक महिला पहलवान हिस्सा लेंगी। मुकाबले अंतरराष्ट्रीय मानकों के मेट पर 28 किलोग्राम से ओपन वर्ग तक कुल 11 भार वर्गों में होंगे। आयोजन समिति की माला ठाकुर ने बताया कि दूरदराज से आने वाली खिलाड़ियों के लिए निशुल्क आवास, भोजन और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली पहलवानों को रेल किराया भी उपलब्ध कराया जाएगा। महिला दर्शकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के साथ परंपरा के प्रतीक पट्टा, त्रिशूल और मुकुट देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और खेल प्रतिभा को नई पहचान देना है।

आईएएस संतोष वर्मा प्रमोशन के मामले में तत्कालीन जिला जज को राहत नहीं

140 फोन कॉल, रिजॉर्ट में मुलाकात, चार्जशीट में कई अहम दावे

इंदौर। चर्चित आईएएस संतोष वर्मा और तत्कालीन जिला न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत से जुड़े मामले में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजेंद्र सिंह रावत को विभागीय कार्रवाई से राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) की चार्जशीट में दर्ज कई तथ्य फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। चार्जशीट में दोनों के बीच संपर्क, मुलाकात और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं। एसआईटी की जांच के अनुसार तत्कालीन जिला न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत और आईएएस संतोष वर्मा के बीच मोबाइल पर लगभग 140 बार बातचीत हुई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इन लगातार संपर्कों के बाद मामले की कार्रवाई में तेजी आई। चार्जशीट के मुताबिक 6 अक्टूबर 2020 को दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई और उसी दिन इंदौर के ग्रैंड माचल रिजॉर्ट में दोनों की मुलाकात भी हुई। एसआईटी ने यह भी उल्लेख किया है कि इसी दिन न्यायाधीश ने न्यायालय से अवकाश लेने के लिए आवेदन दिया था।

निवास के पास फैसले की प्रति सौंपी

चार्जशीट में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार आईएएस संतोष वर्मा की विभागीय पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया से पहले न्यायालयीन आदेश को असाधारण गति से आगे बढ़ाया गया। एसआईटी का दावा है कि 7 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 5:15 बजे न्यायालय की नकल शाखा से आदेश की दो प्रमाणित प्रतियां जारी की गईं। उसी रात लगभग 9 बजे संतोष वर्मा को उनके रेजीडेंसी क्षेत्र स्थित निवास के पास फैसले की प्रति सौंपी गई। इसके अगले दिन 8 अक्टूबर 2020 की सुबह वे आदेश की प्रतियां लेकर भोपाल स्थित सामान्य प्रशासन विभाग पहुंचे और वहां अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

मामला संतोष वर्मा से जुड़ा

यह पूरा मामला वर्ष 2016 में इंदौर के लसूड़िया थाने में एक महिला द्वारा आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। वर्ष 2020 में उनकी पदोन्नति प्रस्तावित थी और इसके लिए इस लंबित प्रकरण का निराकरण आवश्यक माना जा रहा था।

एसआईटी का आरोप है कि इसी कारण मामले के शीघ्र निपटारे के प्रयास किए गए। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी शिकायतकर्ता महिला को मिली तो उन्होंने 9 नवंबर 2020 को न्यायालय की विजिलेंस शाखा और जिला न्यायाधीश के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। बाद में सूचना के अधिकार कानून के तहत भी संबंधित दस्तावेज और जानकारी प्राप्त की गई। मामले ने तूल पकड़ने पर एमजी रोड थाने में कथित फर्जी न्यायिक निर्णय तैयार किए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद एसआईटी ने आईएएस संतोष वर्मा और तत्कालीन जिला न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत को आरोपी बनाते हुए न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। अब हाई कोर्ट द्वारा विजेंद्र सिंह रावत की याचिका खारिज किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, '100 बेड अस्पताल लापता', गुमशुदगी दर्ज करें"

खाली जमीन पर डमी अस्पताल, ठेले पर मरीज, सलाइन का प्रदर्शन

इंदौर। खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित 100 बेड अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी खजराना थाने पहुंचे और प्रस्तावित अस्पताल को 'लापता' बताते हुए उसकी गुमशुदगी दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखित शिकायत व ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के लिए चिन्हित खाली जमीन पर प्रतीकात्मक डमी अस्पताल तैयार किया। यहां ठेले पर मरीज को लिटाकर सलाइन चढ़ाई गई, जबकि डमी डॉक्टरों ने उपचार का नाटकीय प्रदर्शन किया।

नेताओं का कहना था कि यह प्रदर्शन सरकार और प्रशासन का ध्यान खजराना क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में इस क्षेत्र के लिए 100 बेड अस्पताल के निर्माण के साथ 87 डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के पद भी स्वीकृत किए गए थे। इसके बावजूद करीब छह वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्पताल का निर्माण शुरू

नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अस्पताल अस्तित्व में ही नहीं है, तो स्वीकृत डॉक्टर और अन्य स्टाफ वर्तमान में कहां पदस्थ हैं और उनकी सेवाएं किस संस्थान में ली जा रही हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अस्पताल निर्माण में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि अस्पताल नहीं बनने से खजराना और आसपास के लाखों नागरिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। फिलहाल, इस मामले में प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

'नीट-यूजी' में इंदौर के आराध्य गर्ग ने कमाल किया, 110वीं रैंक मिली

कठिन परीक्षा और अनिश्चितता के बावजूद अनुशासित तैयारी

इंदौर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार देर रात नीट-यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष देशभर से लगभग 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 11.21 लाख विद्यार्थियों ने मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता हासिल की है। इंदौर के आराध्य गर्ग ने इस परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया 110 वीं रैंक हासिल की है।

जनरल वर्ग में उन्हें 85वीं रैंक मिली है। इस उपलब्धि के साथ वे इंदौर के टॉपर भी बने हैं। मध्यप्रदेश से इस बार लगभग 1.18 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के आर्यन गुप्ता और

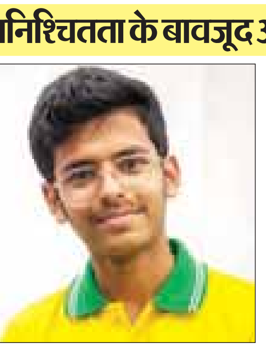

हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। इस वर्ष 19 अभ्यर्थियों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 138 विद्यार्थियों के अंक 690 या उससे अधिक रहे। एनटीए के अनुसार शीर्ष स्थान हासिल करने वाले 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी पहली बार परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 99 प्रतिशत शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच रही। अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आराध्य की सफलता के पीछे लगातार मेहनत और अनुशासित दिनचर्या रही। उनके पिता योगी गर्ग ने बताया कि उनका बेटा शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रहा है।

पिछले वर्ष परीक्षा रद्द होने और लंबे समय तक बनी अनिश्चितता के बावजूद उसने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी। पिछले प्रयास में उसके 700 से अधिक अंक आए थे, जबकि इस बार अपेक्षाकृत कठिन प्रश्नपत्र के बावजूद उसने 690 अंक हासिल किए। उन्होंने बताया कि आराध्य अपनी कोचिंग के टॉप मेरिट बैच का हिस्सा था, जहां उसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप विशेष मार्गदर्शन और उन्नत स्तर की तैयारी कराई गई।

सुरक्षा को लेकर गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं पहुंचीं कलेक्टर कार्यालय

कॉलेज के बाहर अश्लील हरकतें और अभद्र टिप्पणियां

इंदौर। शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर के बाहर बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज के बाहर आए दिन कुछ असामाजिक तत्व उन्हें परेशान करते हैं। उनके बीच भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। उन्होंने प्रशासन से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज के बाहर कुछ युवक रोजाना उनका पीछा करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और अश्लील इशारों के माध्यम से उन्हें परेशान करते हैं। उनका आरोप है कि कई युवक मोबाइल फोन पर अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर छात्राओं को असहज करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी अशोभनीय हरकत की जाती हैं, जिससे कॉलेज आने-जाने वाली छात्राओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सुरक्षा के इंतजाम नहीं

छात्राओं के अनुसार कॉलेज में लगभग 10 हजार छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से इस समस्या को लेकर कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है। हालांकि शुरुआती दिनों में कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस की सक्रियता कम हो जाती है और हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंची छात्राओं ने मांग की कि कॉलेज परिसर और उसके आसपास नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए।

छात्राओं की मांग- साथ ही पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, महिला पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती की जाए और छात्राओं से छेड़छाड़ तथा अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर और लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक छात्रा का अधिकार है और प्रशासन को इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि छात्राओं की शिकायत गंभीर है और प्रशासन इसे प्राथमिकता के आधार पर देखेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जांच कर आवश्यक और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देने की बात कही।

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, बुलडोजर चलेगा, कलेक्टर के निर्देश

सरकारी जमीन पर कब्जा किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा

इंदौर। जिले में अवैध कॉलोनियों की बसाहट और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन अब पूरी सख्ती के मूड में है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी नई अवैध कॉलोनी को विकसित नहीं होने दिया जाए। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शासन की प्राथमिकता वाले मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग कर तय समय सीमा में उसका समाधान किया जाए। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक जवाब देकर शिकायतों का निराकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को नागरिकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने और लंबित प्रकरणों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर कलेक्टर ने सहायक आयुक्त नीरज पाराशर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

किसानों की मांगों पर ध्यान दे सरकार

यह अपने आप में विडंबना ही है कि बुधवार को मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश में बलराम कृषक दिवस का शुभारंभ कर रही थी, उसी वक्त नर्मदा पट्टी के तमाम किसान मूंग की सौ फीसदी खरीद एमएसपी पर करने तथा खाद की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। किसानों का यह आंदोलन अभी जारी है और राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशील रवैया रखती है। उल्टे इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश जरूर हो रही है। जबकि सरकार के रवैये से नाराज किसानों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। किसान संगठन जगह जगह हाई वे जाम कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने दे रहे हैं। नर्मदापुरम में तो उन्होंने कलेक्टोरेट पर अर्द्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया। जबकि सिवनी मालवा में किसानों ने मूंग से भरी बोरी को ही दूल्हा बनाकर अनोखी बारात निकाली। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो अब वो रेल पटरियों पर धरना देकर रेलें रोकेंगे। इस आंदोलन में भारतीय किसान संघ, किसान यूनियन, किसान कांग्रेस और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ सहित कई किसान संगठन शामिल है। किसानों का यह आंदोलन 6 जुलाई से चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने साल कुल उत्पादन की केवल 25 फीसदी मूंग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का निर्णय लिया है। चूंकि इस साल मूंग की बंपर फसल आई है, ऐसे में किसानों को बाकी उपज खुले बाजार में औने-पौने दामों में बेचनी पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में इस वर्ष 18 लाख टन मूंग की पैदावार हुई। भारी उत्पादन के कारण बाजार में मूंग के दाम बहुत गिर गए हैं। किसान अगर इस भाव पर माल बेचता है तो उसे भारी नुकसान होगा। यानी लागत निकलना भी मुश्किल है। जबकि सरकार ने 25 फीसदी उपज ही एमएसपी पर खरीदने की बात कही बल्कि खरीदी के साथ यह शर्त भी जोड़ दी है कि प्रति एकड़ केवल 1.2 क्विंटल मूंग ही खरीदी जाएगी। सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन बाजार में मूंग का भाव केवल 6 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। सरकार की दिक्कत हो सकती है कि वह इतने बड़े पैमाने पर मूंग की खरीदी एमएसपी पर कैसे करे? इसके लिए भी पैसा चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार ने ही कहा था कि वह मूंग की खरीदी एमएसपी पर करेगी। गौरतलब है कि नर्मदा पट्टी के किसान मूंग के रूप में गर्मियों में तीसरी फसल ले रहे हैं। इससे मिला पैसा ही वो खरीफ पर खर्च करते हैं। अगर मूंग बहुत कम भाव पर बिकी तो उन्हें घाटा होना तय है। यहां समस्या केवल भाव की ही नहीं है, समय पर बीज न मिलना, प्रामाणिक बीज मुश्किल से मिलना, सही वक्त पर पर्याप्त खाद न मिलना और अगर मौसम मेहरबान भी रहा तो अच्छी फसल आने के बाद बाजार में भावों का गिर जाना भी बड़ी समस्या है। एक और दिक्कत खरीदी गई फसल के समुचित भंडारण की भी है। दरअसल सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन उसके व्यावहारिक और जरूरी पक्ष को नजरअंदाज कर देती है। मूंग प्रकरण में भी सरकार भले ही पूरी फसल एमएसपी पर न खरीदे, लेकिन कम से कम आधी फसल खरीद कर किसानों को कुछ तो राहत दे। किसानों के प्रति असंवेदनशीलता सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि राज्य में अगले साल पंचायतों के चुनाव होना है।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अखिलेश को 'आंखें' दिखाने का राज

कांग्रेस के कद्दावर नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर की गई तीखी टिप्पणी को इस घटनाक्रम का मुख्य बिंदु माना जा रहा है। मसूद के ये तेवर केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं हो सकते, बल्कि जानकार इसे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर गांधी परिवार की मौन स्वीकृति या उनकी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। इमरान मसूद की पृष्ठभूमि को देखें, तो वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं और उनका आक्रामक तेवर हमेशा से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा रहा है। अखिलेश यादव पर उनका यह प्रहार सपा को असहज करने के लिए काफी है, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल राजनीतिक विश्लेषकों को कांग्रेस के उच्च स्तर तक ले जाता है। दरअसल, कांग्रेस आलाकमान संभवतः यह महसूस कर रहा है कि पिछले कुछ चुनावों में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को न केवल अपनी सीटें गंवानी पड़ीं, बल्कि उसका वोट बैंक भी तेजी से सपा की ओर खिसका है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी जटिलताओं और अप्रत्याशित करवटों के लिए जानी जाती है, और वर्तमान में राज्य में जो सियासी घटनाक्रम घटित हो रहा है, वह उसी परंपरा का एक नया अध्याय है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा अपने ही गठबंधन सहयोगी, समाजवादी पार्टी (सपा) के खिलाफ खोला गया मोर्चा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सतह पर यह एक सामान्य राजनीतिक बयानबाजी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे के निहितार्थ काफी गहरे और दूरगामी हैं। कांग्रेस का यह कदम स्पष्ट रूप से दबाव की राजनीति (प्रेशर पॉलिटिक्स) का एक हिस्सा माना जा रहा है, जहाँ पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जोखिम लेने से भी पीछे नहीं हट रही है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हाशिये पर रही कांग्रेस अब अपनी रणनीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने के संकेत दे रही है। यदि इस स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अब 'हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे' की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर पड़ना तय है।

कांग्रेस के कद्दावर नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर की गई तीखी टिप्पणी को इस घटनाक्रम का मुख्य बिंदु माना जा रहा है। मसूद के ये तेवर केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं हो सकते, बल्कि जानकार इसे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर गांधी परिवार की मौन स्वीकृति या उनकी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। इमरान मसूद की पृष्ठभूमि को देखें, तो वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं और उनका आक्रामक तेवर हमेशा से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा रहा है। अखिलेश यादव पर उनका यह प्रहार सपा को असहज करने के लिए काफी है, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल राजनीतिक विश्लेषकों को कांग्रेस के उच्च स्तर तक ले जाता है। दरअसल, कांग्रेस आलाकमान संभवतः यह महसूस कर रहा है कि पिछले कुछ चुनावों में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को न केवल अपनी सीटें गंवानी पड़ीं, बल्कि उसका वोट बैंक भी तेजी से सपा की ओर खिसका है। ऐसे में यह हमला उस रणनीतिक हताशा और पुनरुत्थान की छटपटाहट का मिश्रण है, जिसे गांधी परिवार द्वारा निर्देशित माना जा रहा है।

राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में 'एकला चलो' की नीति अपनाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा और जोखिम भरा दांव हो सकता है। यद्यपि कांग्रेस का जनाधार इस समय न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन उसके पास खोने के लिए बहुत कम और पाने के लिए बहुत कुछ है। यदि कांग्रेस अकेले लड़ने का निर्णय लेती है, तो वह राज्य में अपनी विचारधारा को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर सकती है और भविष्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को तैयार कर सकती है। हालांकि, यह राह इतनी सरल नहीं है। 'एकला चलो' की राजनीति करने का अर्थ है मुस्लिम और दलित वोटों के उस समीकरण को चुनौती देना, जिसे फिलहाल सपा और बसपा अपनी जागीर समझते हैं। यह प्रयोग सफल होगा या विफल, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह निश्चित है कि इससे विपक्षी एकता का ढांचा बुरी तरह चरमरा जाएगा। कांग्रेस शायद यह मानकर चल रही है कि यदि वह गठबंधन में रहकर अपनी पहचान खो रही है, तो उससे बेहतर है कि अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए, भले ही इसका परिणाम तत्काल न मिले।

दबाव की राजनीति के चश्मे से देखें, तो कांग्रेस का यह रुख सपा को आईना दिखाने जैसा है। सपा ने लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को गठबंधन में तो शामिल किया, लेकिन सीटों के बंटवारे और चुनावी प्रबंधन में उसने कांग्रेस की भूमिका को काफी सीमित रखा। कांग्रेस को यह अहसास हो चुका है कि यदि उसने अभी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया और अपनी ताकत का अहसास सपा को नहीं कराया, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी उसे जूनियर पार्टनर बनकर ही संतोष करना पड़ेगा। इमरान मसूद का हमला इसी असंतोष की अभिव्यक्ति है। यह एक संदेश है कि यदि कांग्रेस की राजनीतिक गरिमा और चुनावी महत्व को नजरअंदाज किया गया, तो गठबंधन के भीतर भी संघर्ष अनिवार्य है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव इस दबाव को झेलते हुए कांग्रेस के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं, या फिर यह दरार और बढ़ती जाती है।

गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। कांग्रेस और सपा दोनों ही इस वोट बैंक को अपना आधार मानती हैं। कांग्रेस का वर्तमान रुख इस वोट बैंक में अपने पुराने वर्चस्व को पुनः प्राप्त करने की कोशिश का एक हिस्सा प्रतीत होता है। यदि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को यह समझाने में सफल रहती है कि सपा केवल सत्ता के लिए उनका उपयोग कर रही है और कांग्रेस उनके दीर्घकालिक हितों के लिए बेहतर है, तो यह समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता फिलहाल सपा के साथ अधिक सहज है, क्योंकि उसे भाजपा को हराने की क्षमता सपा में ही दिखती है। ऐसे में कांग्रेस का 'एकला चलो' वाला दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, यह डर भी कांग्रेस के रणनीतिकारों को सता रहा होगा।

लब्बोलुआब यह है कि कांग्रेस की यह आक्रामक नीति न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता के लिए भी एक परीक्षा है। यदि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा से अलग होती है या उन पर हमलावर बनी रहती है, तो इंडिया गठबंधन की साख पर प्रश्नचिह्न लगना लाजिमी है। यह स्थिति भाजपा के लिए एक प्रकार से उपहार की तरह हो सकती है, क्योंकि विपक्ष का बंटवारा सीधे तौर पर सत्ताधारी दल को मजबूती प्रदान करता है। कांग्रेस का यह कदम एक जुआ है। एक ऐसा दांव, जिसमें जीत की संभावना कम, लेकिन स्वाभिमान की पुर्नस्थापना की ललक अधिक दिखती है। यह रणनीति बताती है कि कांग्रेस अब अपनी खोई हुई विरासत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उसके लिए उसे अपने सहयोगी दलों के साथ रिश्तों को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। आने वाले महीने इस बात के गवाह होंगे कि क्या यह रणनीति कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनः मुख्यधारा में लाती है, या फिर यह उसकी राजनीतिक आत्मघाती भूल साबित होती है।

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

अमेज़न का संकट और वैश्विक उदासीनता

किसी युद्ध की कल्पना करते ही आँखों के सामने टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और धधकते शहरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इक्कीसवीं सदी का एक ऐसा युद्ध भी है, जो बिना औपचारिक घोषणा के लगातार जारी है। इसमें न सेनाएँ आमने-सामने हैं, न सीमाओं पर गोलाबारी हो रही है और न ही किसी देश ने युद्ध का ऐलान किया है। फिर भी इस संघर्ष में हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, समुदाय विस्थापित हो रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह युद्ध दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावनों में चल रहा है।

अमेज़न को पृथ्वी के 'फेफड़े' कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में शामिल यह क्षेत्र वैश्विक जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करोड़ों टन कार्बन को अपने भीतर समेटे यह वन केवल ब्राज़ील की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर है। लेकिन यही जंगल आज आर्थिक हितों और संगठित अपराध के दबाव में लगातार सिकुड़ रहा है।

अमेज़न केवल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं है। लगभग 67 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वनों का लगभग आधा हिस्सा यहीं स्थित है। वैश्विक स्तर पर ज्ञात जैव विविधता की लगभग 10 प्रतिशत प्रजातियाँ अमेज़न में पाई जाती हैं। करीब 4.7 करोड़ लोग, जिनमें 350 से अधिक आदिवासी समुदाय शामिल हैं, इसी पारिस्थितिकी तंत्र पर अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए निर्भर हैं। इसलिए अमेज़न का संकट किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का संकट है।

लंबे समय तक जंगलों को विकास में बाधा माना जाता रहा। सड़कें, खनन, बड़े कृषि फार्म और औद्योगिक परियोजनाएँ आर्थिक प्रगति के प्रतीक बन गईं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रकृति की कीमत पर हासिल विकास अंततः समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को असुरक्षित बना देता है।

ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र में यही स्थिति दिखाई देती है। जंगलों को साफ कर कृषि भूमि बनाई जा रही है, खनिजों के दोहन के लिए बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और लकड़ी का अवैध कारोबार लगातार फैल रहा है। इन गतिविधियों के साथ भूमि पर कब्ज़े, हिंसा और संगठित अपराध का गठजोड़ भी मजबूत हुआ है। जहाँ जंगल कमज़ोर पड़ता है, वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ भी कमज़ोर होती दिखाई देती हैं।

ब्राज़ील के पास्टोरल लैंड कमीशन (सीपीटी) के अनुसार हाल के वर्षों में देश में दर्ज ग्रामीण भूमि-संघर्षों में आधे से अधिक मामले अकेले अमेज़न क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। वर्ष 2024 में 2,185 भूमि-संघर्ष दर्ज किए गए, जिनमें 1,180 मामले अमेज़न क्षेत्र के थे। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है; यह प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई है।

कभी जंगल जीवन का आधार थे, आज वे पूँजी का आधार बनते जा रहे हैं। भूमि पर नियंत्रण का अर्थ अब केवल खेती नहीं रह गया है। उसके साथ खनिज संपदा, जल संसाधन, जैव विविधता, कार्बन बाज़ार, परिवहन मार्ग और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव भी जुड़ गए हैं।

इसी कारण जंगलों में अवैध खनन, लकड़ी की तस्करी, मादक पदार्थों के नेटवर्क और धन शोधन जैसी गतिविधियाँ एक-दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। पर्यावरण अपराध अब अलग-थलग अपराध नहीं रहे; वे संगठित आर्थिक तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं।

यही वजह है कि अमेज़न के अनेक हिस्सों में राज्य की औपचारिक सत्ता से अधिक प्रभाव अपराधी समूहों का दिखाई देता है। नदियाँ परिवहन के प्राकृतिक मार्ग होने के कारण अवैध व्यापार की राह बन जाती हैं और जंगलों के भीतर बसे समुदाय सबसे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। जंगलों की रक्षा करने वाले लोग ही सबसे अधिक खतरे में हैं। आदिवासी समुदाय, नदी किनारे रहने वाले परिवार, वन उत्पादों पर निर्भर समाज और पर्यावरण कार्यकर्ता वर्षों से इन क्षेत्रों की रक्षा करते आए हैं। वे जंगल को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। लेकिन जब जंगल आर्थिक हितों का केंद्र बन जाता है, तो यही समुदाय सबसे पहले निशाने पर आते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता चिको मेंडेस की हत्या 1988 में हुई थी। वे रबर उत्पादक समुदायों और जंगलों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी हत्या ने दुनिया का ध्यान अमेज़न की ओर खींचा, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। आज भी पर्यावरण रक्षकों की हत्या, धमकी और झूठे मुकदमे अनेक देशों में सामान्य घटना बन चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें बताती हैं कि दुनिया भर में पर्यावरण और भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सबसे जोखिम वाले क्षेत्रों में अमेज़न शामिल है।

अमेज़न का संकट केवल जंगलों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। जंगलों की कटाई से वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। वर्षा चक्र प्रभावित होता है और सूखे तथा अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएँ बढ़ने लगती हैं। दूसरी ओर, जब पानी और उपजाऊ भूमि की उपलब्धता घटती है तो प्राकृतिक संसाधनों पर संघर्ष तेज़ हो जाता है।

यानी जलवायु परिवर्तन और हिंसा एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन चुके हैं। पर्यावरण का विनाश केवल पारिस्थितिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का भी कारण बन रहा है।

यह मान लेना आसान होगा कि अमेज़न का संकट केवल ब्राज़ील की नीतियों का परिणाम है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

दुनिया भर के बाज़ारों में पहुँचने वाला गोमांस, सोयाबीन, लकड़ी और खनिजों का एक हिस्सा उन इलाकों से आता है जहाँ वनों की कटाई और भूमि संघर्ष जारी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से इन उत्पादों का व्यापार करती हैं और अंतरराष्ट्रीय निवेश भी इस प्रक्रिया को गति देता है।

इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल स्थानीय कानूनों से संभव नहीं होगा। वैश्विक व्यापार, निवेश और कॉरपोरेट जवाबदेही को भी इसमें शामिल करना होगा। यदि बाज़ार जंगलों के विनाश से लाभ कमाता रहेगा तो संरक्षण के प्रयास अधूरे रहेंगे।

अमेज़न की कहानी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला परियोजनाओं को लेकर विवाद, पश्चिमी घाट में विकास और संरक्षण के बीच टकराव तथा हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण–ये सभी उदाहरण बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर संघर्ष केवल दक्षिण अमेरिका तक सीमित नहीं है।

भारत ने वनाधिकार कानून, ग्राम सभा की भूमिका और जैव विविधता संरक्षण जैसी अनेक प्रगतिशील व्यवस्थाएँ विकसित की हैं। लेकिन इनका प्रभाव तभी दिखाई देगा जब स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया का वास्तविक भागीदार बनाया जाएगा।

अनुभव बताता है कि जहाँ समुदायों को जंगलों के संरक्षण का अधिकार और दायित्व मिला, वहाँ वनों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है। संरक्षण ऊपर से थोपा गया कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्थानीय भागीदारी पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया होना चाहिए।

अमेज़न का संदेश यही है कि पर्यावरण को अब केवल पेड़-पौधों का विषय मानकर नहीं देखा जा सकता। यह अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।

यदि जंगल समाप्त होते हैं तो केवल जैव विविधता नहीं घटती; जल स्रोत सूखते हैं, कृषि प्रभावित होती है, विस्थापन बढ़ता है और सामाजिक संघर्ष गहराते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण विकास का विरोध नहीं, बल्कि विकास की पूर्वशर्त है।

आज दुनिया को ऐसे विकास मॉडल की आवश्यकता है जिसमें आर्थिक समृद्धि और पारिस्थितिक संतुलन साथ-साथ चल सकें। अन्यथा अमेज़न में दिखाई दे रहा संकट आने वाले दशकों में एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य वन क्षेत्रों की भी वास्तविकता बन सकता है।

अमेज़न का मौन युद्ध याद दिलाता है कि सभ्यता का भविष्य केवल सीमाओं की सुरक्षा से तय नहीं होगा। वह इस बात से भी तय होगा कि हम अपने जंगलों, नदियों और उन समुदायों की कितनी रक्षा कर पाते हैं जो सदियों से प्रकृति के सबसे विश्वसनीय संरक्षक रहे हैं। यदि इस चेतावनी को समय रहते नहीं समझा तो इतिहास यह दर्ज करेगा कि मानवता ने अपने सबसे बड़े युद्ध को पहचाना तब, जब बहुत देर हो चुकी थी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

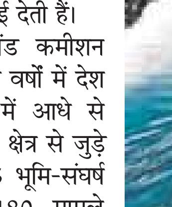

सुधीर देशपांडे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सचमुच, तुम्हें फोटो खींचना ही नहीं आता

पर्यटन में, कहते हैं एक साथी हो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाता है। कहते हैं साथी तो हो, पर पत्नी न हो। सयाने लोग तो ये भी कहते हैं, यदि साहित्य में नाम करना हो तो पत्नी के अलावा भी एक होना चाहिए, जिसे आप अपने मन की बात कह सको। इस मामले में दोस्तों के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है। वे साथी और दोस्त में फर्क करते हैं। साथी वो जो साथ रहे। हर दोस्त, साथी नहीं होता और हर साथी, दोस्त नहीं होता। ज्ञानीजी का मानना है कि पत्नी चूंकि साथ रहती है, इसलिए साथी हो सकती है। दोस्त नहीं हो सकती। यदि दोस्त भी बन जाए तो यह ग्रह नक्षत्रों का चमत्कार ही मानना चाहिए। साथी के बारे में उनके उपनिषद् होकर ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होना यह भी दुर्लभ है। बस, यह अवसर तब मिला, जब दो एक स्थलों का भ्रमण करने के बाद थक हार कर एक वृक्ष के नीचे रखी बैंच पर बैठना हुआ। पड़ोस में ही एक श्वेतकेश राशि वाले सज्जन बैठे हुए थे। मुख मुद्रा गंभीर थी।

मैंने पूछा - 'आप भी?'

'मतलब?' थके हुए अंदाज में उन्होंने कहा।

'आप भी घूमने आए हैं?' मैंने कहा

'बिल्कुल, बल्कि यह कहो घुमाया जा रहा हूँ।' अब तक क्या क्या देख लिया।

'देखने, समझने और अपने चित्त की शांति के लिए आया था। पर जो देखा है, वह तो घर पर बैठकर भी देख सकता था। लगता है ग़लत आ गया। तुम्हारी कहो।'

'आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं न?' 'एक उम्र के बाद और शादी के बाद हर आदमी के विचार एक दूसरे से मिलने लगते हैं।' चिंतन की मुद्रा धारण करते हुए उन्होंने कहा। 'हाँ, यह तो है।' मैंने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा- 'वैसे आपका दुःख क्या है? 'वही जो तुम्हारे! बताओ, योजना कहाँ की बनी थी?' उन्होंने पूछा।

'अंऽ... !'

'भूल गये न?'

'भूला तो नहीं पर ...।'

'बहाने मत बनाओ, दोस्त। हाँ, हमने याने तुमने भी प्लान यह किया था कि हम इस बेहतरीन जगह को जहाँ एक ओर समुद्र की लहरें होंगी और दूसरी तरफ हरियाली। कुछ रोमांचक दृश्य होंगे। कुछ रोमांटिक समां। बोलो यही कुछ सोचा था न?'

'हाँ, हाँ! बिल्कुल यही सोचा था। पर सोचने से क्या होता है?'

'सच है, सोचना एक बात है और होना दूसरी बात। तुम ज्योतिषी हो या कोई दृष्टा, जो तड़ातड़ मेरे मन की बात ताड़ रहे हो। ' वह हँस दिया- 'कहा तो सही, हर शादीशुदा आदमी की समस्याएँ भी और सोच भी एक ही हो जाती है।'

'अच्छा बताओ कुछ देखा भी कि फोटो खींचते रहे।'

मैं उनके इस कथन से गश खाकर गिरते गिरते बचा।

'सच कहूँ तो मन में यही भाव लेकर चला था कि सपत्नीक घूमेंगे। श्रीमतीजी और मैं दोनों इस हसीन से कहे जाने वाले नजारे को देर तक हाथ में हाथ डाले, टहलते, या किसी जगह इत्मीनान से बैठकर तकेंगे। डूबती उतराती लहरों का नर्तन देखेंगे। उसके कल-कल निनाद और बूंदों का स्पर्श अनुभव करेंगे। फिर दूर तक चलते हुए किसी पहाड़ी इलाके में सूर्योदय और सूर्यास्त को तकेंगे। यही जीवन के उत्थान और पतन के साम्य को देखेंगे।' मैंने कहा। वे भी उछल कर बोले- 'एक्जेक्ट। यही मैं भी सोचकर निकला था। पर... 'सुनो तो।' एक नहीं एक साथ दो नारी स्वर गूँज उठे। हम दोनों ही चौंककर खड़े हो गये। हम दोनों तो संयोग से एक दूसरे से मिले थे पर ये दोनों भी ...!

'मैंने कहा था न? हमारे इनको जरा भी रूचि नहीं है। ये सारे नजारे छोड़कर यहाँ बैठे हैं।' मेरी श्रीमती मेरे पास आकर बोली।

'मेरे भी तो! वो मेरे हैं।' मेरे साथ बैठे सज्जन की ओर इशारा करते हुए सज्जन की ओर करते हुए दूसरी ने चहकते हुए कहा। चलो न दो तीन सेल्फी पाइंट है, वहां पर फोटो लेते हैं। बस मना मत करना।' पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं के याद आते ही हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मना कर पाते। और दोनों ही चुपचाप उनके साथ चल पड़े। उन्होंने जितने चाहे, जैसे चाहे, उतने फोटो खींचे। पूरी यात्रा में हमारी भूमिका भी फोटोग्राफर की थी। वापसी पर वे फोन की गैलरी में मेरे खींचे फोटो देखकर बोली- सचमुच, तुम्हें फोटो खींचना ही नहीं आता। शायद इसे ही कहते हैं- 'मुर्गी की जान गई पर खानेवाले को मजा ही नहीं आया।'

केवल दक्षिण अफ्रीका नहीं, पूरी मानवता के साझा नायक

नेल्सन मंडेला दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

यह दिवस केवल उनकी जयंती भर नहीं है बल्कि एक वैश्विक अपील है कि समाज, देश और विश्व में परिवर्तन लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आगे आए। यह दिन हमें यह याद दिलाने आता है कि परिवर्तन के लिए केवल भाषण नहीं, कर्म और समर्पण चाहिए। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में स्थित म्वेजो नामक गांव में हुआ था। वे 'थेम्बू' जातीय समुदाय की 'मदिवा' शाखा से संबंधित थे। उनका मूल नाम रोहिलाहला मंडेला था, जिसका अर्थ होता है शरारती या पेड़ की टहनी हिलाने वाला। स्कूल में एक अंग्रेज शिक्षक ने उन्हें 'नेल्सन' नाम दिया था क्योंकि उस समय अश्वेत छात्रों को अंग्रेजी नाम देना आम परंपरा थी। उनका बचपन एक सामान्य अफ्रीकी बच्चे की तरह बीता लेकिन उनके भीतर अन्याय के प्रति तीव्र संवेदनशीलता, नेतृत्व की भावना और सच्चाई के लिए लड़ने का साहस जन्म से ही था। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबरी मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय, जोहान्सबर्ग से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी।

विश्व इतिहास में नेल्सन मंडेला का नाम केवल एक नेता या राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि मानवता, समानता, सहिष्णुता और साहस के प्रतीक के रूप में अंकित है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि विचारों और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने वाला व्यक्ति न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को 'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस केवल उनकी जयंती भर नहीं है बल्कि एक वैश्विक अपील है कि समाज, देश और विश्व में परिवर्तन लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आगे आए। यह दिन हमें यह याद दिलाने आता है कि परिवर्तन के लिए केवल भाषण नहीं, कर्म और समर्पण चाहिए। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में स्थित म्वेजो नामक गांव में हुआ था। वे 'थेम्बू' जातीय समुदाय की 'मदिवा' शाखा से संबंधित थे। उनका मूल नाम रोहिलाहला मंडेला था, जिसका अर्थ होता है शरारती या पेड़ की टहनी हिलाने वाला। स्कूल में एक अंग्रेज शिक्षक ने उन्हें 'नेल्सन' नाम दिया था क्योंकि उस समय अश्वेत छात्रों को अंग्रेजी नाम देना आम परंपरा थी। उनका बचपन एक सामान्य अफ्रीकी बच्चे की तरह बीता लेकिन उनके भीतर अन्याय के प्रति तीव्र संवेदनशीलता, नेतृत्व की भावना और सच्चाई के लिए लड़ने का साहस जन्म से ही था। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबरी मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय, जोहान्सबर्ग से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उस समय दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा 'अपरथाइड' नामक क्रूर नस्लीय व्यवस्था लागू थी, जिसके तहत श्वेतों को सभी अधिकार प्राप्त थे और अश्वेतों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। अश्वेतों को न तो मतदान का अधिकार था, न सार्वजनिक सेवाओं का और न ही भूमि पर अधिकार। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया था। उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ मंडेला ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और युवा विंग की स्थापना की। उन्होंने शुरू में अहिंसात्मक विरोध और शांतिपूर्ण आंदोलनों का मार्ग अपनाया लेकिन जब सरकार ने उन प्रयासों को कुचलने के लिए बर्बरता की हदें पार कर दी, तब मंडेला ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और 'उमखोंतो वे सिजवे' नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने अफ्रीका में रंगभेद व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बनकर कार्य किया।

1962 में मंडेला को देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने जेल में 27 वर्ष बिताए, जिनमें से अधिकांश समय उन्होंने रोबेन द्वीप की कोठरी में गुजारा। वहां न बिजली थी, न बिस्तर, न पढ़ने के अधिक साधन लेकिन उन्होंने अपने विचारों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। जेल में रहकर उन्होंने अन्य कैदियों को शिक्षित किया, कानूनी किताबें पढ़ी और राजनीतिक सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। बाहर दुनिया बदल रही थी और मंडेला की रिहाई की मांग दुनियाभर में उठने लगी थी। उनके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनने लगा। अंततः 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्हें देखते ही लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। वह क्षण केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए ऐतिहासिक था। जेल से निकलने के बाद उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया बल्कि क्षमा और मेल-मिलाप की राजनीति को अपनाया। उन्होंने नफरत के बदले संवाद, प्रतिशोध के बदले न्याय और विभाजन के बदले एकता को चुना। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को फिर से संगठित किया और देश को एकजुट करने के लिए 'सत्य और मेलमिलाप आयोग' की स्थापना की, जहां अपराधी और पीड़ित आमने-सामने बैठकर अपने अपराधों को स्वीकार करते और क्षमा मांगते थे। मंडेला के जीवन और कार्यों की प्रेरणा अफ्रीकी दर्शन 'उबुन्टु' में निहित थी, जिसका सार है 'मैं हूं क्योंकि हम हैं।' उनके नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि बदले की भावना से देश नहीं बनते बल्कि माफी और मेल-मिलाप की भावना ही राष्ट्र निर्माण की असली नींव होती है।

1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बहुजातीय लोकतांत्रिक चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह केवल एक राजनीतिक पद नहीं था बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए सुलह, समरसता और सामाजिक न्याय की नीति अपनाई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व का अर्थ केवल शासन करना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होता है। वे एक कार्यकाल के बाद ही राष्ट्रपति पद से हट गए जबकि चाहते तो आजीवन सत्ता में बने रह सकते थे।

उनके योगदानों के लिए उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1990 में भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और यह सम्मान पाने वाले वे पहले विदेशी बने। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन सहित कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जुलाई को 'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित किया ताकि लोग उनके जीवन और दर्शन से प्रेरणा लेकर समाज के लिए कार्य करें। इस दिन संयुक्त राष्ट्र ने आग्रह किया है कि लोग कम से कम 67 मिनट समाजसेवा में दें, जो मंडेला के सार्वजनिक जीवन के 67 वर्षों का प्रतीक है। नेल्सन मंडेला का जीवन आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने यह साबित किया कि नेतृत्व केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। उन्होंने यह सिखाया कि असहिष्णुता और अन्याय का मुकाबला नफरत से नहीं बल्कि साहस और संवेदनशीलता से किया जा सकता है। जब उन्होंने कहा, 'मैंने पाया कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है' तो यह महज शब्द नहीं थे बल्कि उनके जीवन का अनुभव था। उन्होंने यह भी कहा था कि बहादुर वह नहीं होता, जो डरता नहीं बल्कि वह होता है, जो डर को जीतता है। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। उनके निधन के समय दुनिया के सभी कोनों से श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें 'दक्षिण अफ्रीका का गांधी', 'मानवता का प्रकाश स्तंभ' और 'सद्भावना का प्रतीक' कहा गया। उनके नाम पर दुनियाभर में विश्वविद्यालय, संस्थान, सड़कें और पुरस्कार हैं। उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित हैं। आज जब दुनिया असमानता, नस्लवाद, युद्ध और कट्टरता की चुनौतियों से जूझ रही है, तब नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं की दृष्टि, सोच और मार्गदर्शन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। वे हमें सिखाते हैं कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, एक मोमबत्ती उसे चीर सकती है। उनका यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है 'एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक विजयी संयोजन होता है।' यदि हम आज भी दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की मानवता, साहस और करुणा को जाग्रत करना होगा और यही नेल्सन मंडेला को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा के मायने

विश्व राजनीति

दुर्गेश्वर राय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संयोजक हैं।

सोशल मीडिया पर हाल ही में बलूचिस्तान की आजादी से जुड़ा एक पत्र तेजी से वायरल हुआ। इस पत्र में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन और नई मुद्रा जारी करने का दावा किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं और वैश्विक मीडिया ने इस दावे को पूरी तरह अपुष्ट और इंटरनेट प्रोपेगैंडा माना है। जमीनी स्तर पर बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की माँग को लेकर संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। इस संघर्ष के पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण मौजूद हैं।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक राजनीति की कसौटी पर किसी भी क्षेत्र के लिए एक नए देश का दर्जा पाना आज के दौर में बेहद दुरूह है। मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार किसी नए राष्ट्र के लिए स्थायी आबादी, निश्चित भूभाग, प्रभावी सरकार और विदेशी संबंध बनाने की क्षमता जैसे बुनियादी मानकों को पूरा करना होता है। बलूचिस्तान के पास आबादी और भूभाग तो है, लेकिन वहां एक संप्रभु और प्रभावी प्रशासनिक सरकार की स्थापना करना पाकिस्तानी सैन्य नियंत्रण के रहते व्यावहारिक रूप से असंभव बना हुआ है हालांकि पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण लगातार खोता जा रहा है। इसके आगे की बाधा और भी विकट है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी और महासभा के दो-तिहाई देशों का समर्थन आवश्यक होता है। बलूचिस्तान के संदर्भ में, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन अपने विशाल आर्थिक हितों और सी.पी.ई.सी. परियोजना को बचाने के लिए किसी भी स्वतंत्रता प्रस्ताव पर तुरंत अपने वीटो का इस्तेमाल कर उसे निरस्त कर देगा। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी संप्रभु देश की प्रादेशिक अखंडता को प्राथमिकता देती है, इसलिए जब तक मूल देश स्वयं विभाजित होने की अनुमति न दे या उसका पूर्ण विघटन न हो जाए, तब तक एकतरफा स्वतंत्रता को वैश्विक मान्यता मिलना लगभग नामुमकिन होता है।

बलूचिस्तान के विद्रोह का इतिहास विभाजन के समय से शुरू होता है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जब अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया तो कलात रियासत ने अपनी स्वतंत्रता चुनी थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलपूर्वक इसका विलय कर लिया। इसके बाद 1954 से 1958 के बीच पाकिस्तान की वन-यूनिट पॉलिसी के विरुद्ध दूसरा बड़ा विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नवाब नौरोज खान ने किया। वर्ष 1963 से 1970 के दौरान सेना की वापसी की माँग को लेकर बलूच कबायली नेताओं ने शेरों मूरी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। इन दोनों ही चरणों में बलूच नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाकर गिरफ्तार किया गया या फांसी दे दी गई, जिससे बलूच जनता में अविश्वास की खाई और गहरी हो गई। वर्ष 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त किया, तब बांग्लादेश से प्रेरित होकर चार वर्षीय स्वायत्तता आंदोलन छिड़ गया। वर्ष 2000 के बाद से विद्रोह की पाँचवीं लहर चल रही है, जिसमें सैन्य ज्यादतियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर असंतोष चरम पर है।

इस असंतोष का एक बड़ा कारण आर्थिक शोषण और मानवाधिकारों का हनन है। बलूचिस्तान खनिज संसाधनों के मामले में अत्यधिक समृद्ध है, लेकिन यह पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस, तांबा और सोने के भंडार हैं, परंतु इसका स्थानीय लाभ न्यूनतम है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और ग्वादर बंदरगाह जैसी बड़ी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी न के बराबर है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 से अब तक 10,000 से अधिक बलूच नागरिक लापता हो चुके हैं, जिन्हें जबरन गायब करने और फर्जी मुठभेड़ों में मारने के आरोप पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगते रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा के कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अल-कायदा जैसे उग्रवादी समूहों की सक्रियता भी बढ़ी है, जिससे शिया समुदायों पर सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं।

बलूचिस्तान के अलग होने या अस्थिर होने का सीधा प्रभाव उसके पड़ोसियों और वैश्विक शक्तियों पर पड़ता है। चीन ने सी.पी.ई,सी. और ग्वादर में भारी निवेश किया है, जिससे उसकी सीधी पहुंच अरब सागर तक होती है। बलूचिस्तान में अस्थिरता से चीन के आर्थिक हितों को गहरा धक्का लग रहा है।

जहाँ तक भारत के रुख का प्रश्न है, भारत इस पूरे मामले में एक सतर्क दृष्टिकोण रखता है। भारत बलूचिस्तान में किसी भी तरह के सीधे हस्तक्षेप से इनकार करता है और पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करता है। भारत का मानना है कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है जिसे उन्हें स्वयं हल करना चाहिए। हालांकि, वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत के अनुरूप है। भारत वैश्विक मंचों पर हमेशा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के भीतर रहकर क्षेत्रीय स्थिरता और बलूच नागरिकों के अधिकारों की पैरवी करता है। वैश्विक मंतव्य भी यही है कि बलूचिस्तान में हिंसा और सैन्य दमन रुकना चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया में सुरक्षा की चुनौतियां और अधिक गंभीर न हों।

बारिश की खेंच और यादों की बरसात

विचार

सुरेश उपाध्याय

लेखक स्तंभकार हैं।

मालव धरती गहन गम्भीर - डग-डग, रोटी पग-पग नीर' यह कहावत मालवा की पहचान और उसकी सम्पन्नता की प्रतीक रही है। अलनीनो की चर्चा, खंडवर्षा की सम्भावना, अभी तक कम वर्षा के आंकडे और बारिश की खेंच ने यादो की बरसात को ताजा कर दिया है। आषाढ के घने काले बादल, सावन के सैरे, भादवा की झड़ी के उस दौर में कई दिनों तक सूरज अवकाश पर चला जाता था। बरसात सीजन भर होती थी, स्कूलों में हफ्ता की छुट्टी भी हो जाती थी। भजिए, गुलगुले, नमकीन/मीठे रेलमे (ताये) व गुडराब स्वाद के अतिरिक्त मौसम के मुकाबले की खुराक (प्रीवेंटिव मेडिसिन) हुआ करती थी। वर्षा जल से लबालब तालाब, उफनती नदियों का विभिन्न शहरों में प्रवेश व तांडव तथा प्राकृतिक झरनो का सौंदर्य सुर्खियों व जनचर्चा में रहता था। इतना बरसा पानी जल स्रोतों में एकत्र रहता था और वाष्पीकरण के चलते पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया होती थी। पानी घरों तक पहुंचाने की नल व्यवस्था पर्याप्त नही थी। पीने का पानी शहर के कुंओं से भर कर कावडिए वर्षभर सम्पन्नों के घर घर पहुंचाते थे। नहाने व कपड़े धोने के लिए नदी घाट, कृत्रिम कुंड व तालाब की राह अलसुबह से हलचल शुरु हो जाती थी। ग्रीष्म ऋतु के आते-आते संकट और बढ जाता था। सरकारी हैंडपंप पर दिन उगने से पहले नम्बर लगते जो देर रात तक चलते रहते थे। निजी हैंडपंप भी कम मात्रा में थे और पास पडोस के लिए वे उदार रहते थे। सडक पर नगरपालिका से मशक के माध्यम से छिड़काव होता था। मां, बहन, बेटी, भाभी पडोस के कुंओं, झीन की बावडी व पथवारी के हैंडपंप से घड़े-गगरे उठाए चली आती थी, चुमली बनाने व एक के ऊपर एक बर्तन रखने की मदद सहर्ष की जाती थी। बच्चों व युवाओं के जिम्मे हैंडपंप चलाने का जिम्मा रहता था। कुंए में डूबे बाल्टी व बर्तन के लिए लोहे के हुक लगे कांटे का प्रयोग होता था। कुछ उसके विशेषज्ञ भी होते थे। कुंओं में गंठे, नदी-तालाब में डाइ व बरछी लगाने का सबका अपना अपना अंदाज होता था। जल स्रोतों पर अच्छी खासी रौनक व मेल-मिलाप के साथ सुख-दुःख की बातें होती, गॉसिप भी होती ही थी। पीने के पानी की स्थाई व अस्थाई प्याऊ और उस पर सेवा को धर्म की तरह किया जाता था। पशुओं व पक्षियों के लिए सभी गलियो में व्यवस्था होता थी।

अब जब पारिस्थितिकी तंत्र से छेडछाड के दुष्परिणाम सामने आए हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाए हैं, वर्षा ऋतु के माने बदल गए हैं। नदी, तालाब, कुंओं, बावडियों पर अतिक्रमण, उनमें अवशिष्ट व अपशिष्ट के छोडे जाने, उनके उथले व संकीर्ण किए जाने, उनकी अवहेलना किए जाने की प्रक्रिया ने गम्भीर संकट खडे कर दिए हैं। बाढ़ अब भी आती है, खतरे के निशान बदल गए है और पानी उन तक जल्दी पहुंचता भी है। थोडी वर्षा में स्मार्ट शहर तक डूब जाते हैं। पानी की घर-घर नल पहुंच की पहल के बावजूद पीने के शुद्ध पानी का संकट चौतरफा नजर आता है। वर्षभर टेंकर से सप्लाय, टेंकर पर युद्ध की स्थितियां व निजी टेंकरों की व्यावसायिकता आज आम बात है। संकट का हल खोजने में नलकूपों की अंधाधुंध खुदाई ने जलस्तर को रसातल में पहुंचा दिया है। पानी एक कमोडिटी बन कर रह गया है। पानी विभिन्न साइज की बोतल, पाउच, केन से बिकने वाली वस्तु में तब्दिल हो गया है और जल शुद्धिकरण यंत्रों को घर-घर की आवश्यकता बना दिया गया है। एक बड़ा बाजार व व्यवसाय तंत्र पानी के नाम पर खड़ा हो गया है और ऐसे में खंडवर्षा, कुछ दिनो में पूरी सीजन की वर्षा, अल नीनो के प्रभाव ने आसन्न संकट व चुनौतियों को सामने ला दिया है। यह स्मरण रहना चाहिए कि 'पानी से पैसे तो बनाए जा सकते हैं लेकिन पैसे से पानी नहीं बनाया जा सकता है'। बोए गए बीज खराब होने की खबरे भी है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के समक्ष भी चुनौती हो सकती है। समय रहते इन तात्कालिक चुनौतियों से निपटने की तैयारी के साथ जल, जंगल, जमीन के संरक्षण व संवर्धन के लिए दीर्घकालीन नीतियां व कार्यक्रम अपनाने की जरुरत है। इस दिशा में ठोस, गम्भीर व उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास की दरकार है।

सौरव गांगुली की बायोपिक के पोस्टर से माहौल बनाने की चेष्टा

फिल्म समीक्षा

आदित्य दुबे

लेखक वेबसाइट ई अंतर्भव के प्रबन्ध संचालक हैं।

पोस्टर में राजकुमार राव का लुक युवा सौरव गांगुली की याद दिला रहा है। इसके लिए अभिनेता ने केश सज्जा (हेयरस्टाइल), चेहरे के हाव भाव और देह भाषा (बॉडी लैंग्वेज) पर खास काम किया गया है। फिल्म का पोस्टर रिलीज करने के साथ ही बायोपिक के निर्माता ने इसक प्रदर्शन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 14 मई 2027 को रिलीज होगी। दस महीने का लम्बा अन्तराल इस बायोपिक के लिये माहौल बनाने में भले ही सहायक हो मगर इस गेप में इस बायोपिक के प्रति दर्शकों में उत्साह बनाये रखना बेहद कठिन होगा।अब यह वक्त ही बताएगा कि निर्माता-निर्देशक का यह दावा कितना सफल रहता है?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली की बायोपिक - 'दादा- द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक इसी सप्ताह दर्शकों के सामने आ गया है। फिल्म का शीर्षक -'दादा' है जिसकी टैगलाइन भी काफी जोरदार है - उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, खेल को बदल दिया। फिल्म के पहले प्रदर्शित पोस्टर में सौरव की भूमिका निभाने वाले अभिनेता राजकुमार राव, सौरव के सबसे यादगार पल को पुनर्रचित (रीक्रिएट) करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में राजकुमार राव का लुक युवा सौरव गांगुली की याद दिला रहा है। इसके लिए अभिनेता ने केश सज्जा (हेयरस्टाइल), चेहरे के हाव भाव और देह भाषा (बॉडी लैंग्वेज) पर खास काम किया गया है। फिल्म का पोस्टर रिलीज करने के साथ ही बायोपिक के निर्माता ने इसक प्रदर्शन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 14 मई 2027 को रिलीज होगी। दस महीने का लम्बा अन्तराल इस बायोपिक के लिये माहौल बनाने में भले ही सहायक हो मगर इस गेप में इस बायोपिक के प्रति दर्शकों में उत्साह बनाये रखना बेहद कठिन होगा।अब यह वक्त ही बताएगा कि निर्माता -निर्देशक का यह दावा कितना सफल रहता है?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का गत सात जुलाई को चौपनवां जन्मदिन था, इस खास मौके पर बायोपिक के निर्माता ने सौरव गांगुली की भूमिका निभा रहे अभिनेता राजकुमार राव का पहला लुक रिलीज किया जो बायोपिक के बारे में उम्मीद जगाने वाला है । इस फिल्म के निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी हैं और निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं। फिल्म को टी-सीरीज, डीबीएल और लव फिल्म्स मिलकर बना रहे हैं। पोस्टर ज़ारी होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में गांगुली ने कहा कि इस मौके ने उनके जन्मदिन को और भी खास बना दिया है। इससे मेरा बर्थ डे और भी यादगार बन गया है. यह सच में अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। उन्होंने कहा यह पोस्टर मुझे मेरे क्रिकेट सफर के एक बेहद खास पल में वापस ले जाता है । राजकुमार ने इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है. मुझे भरोसा है कि वह मेरी कहानी को दर्शकों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाएंगे।

वर्ष 2021 में सौरव ने अपनी बायोपिक का एलान किया था। बायोपिक में सौरव की शुरुआती जिंदगी से उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने तक की कहानी नजर आएगी। बायोपिक का बजट बड़ा बताया जा रहा है। फिल्म में गांगुली के क्रिकेट कैरियर के अहम पड़ावों को दिखाया जाएगा। इसमें उनके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने, जीवन के संघर्ष और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को भी दिखाया जाएगा। सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और प्रभावशाली कप्तानों में गिना जाता है। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी आक्रामक कप्तानी और बेखौफ सोच से टीम इंडिया को नई पहचान दिलाई थी ।उनके नेतृत्व में भारत ने विदेशों में कई यादगार सफलताएं हासिल कीं. इनमें वर्ष 2004 में पाकिस्तान में पहली बार टेस्ट सिरीज की जीत और वर्ष 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सिरीज ड्रॉ कराना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2001 में भारत ने घरेलू टेस्ट सिरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर उसकी लगातार 15 टेस्ट मैचों की जीत का सिलसिला भी खत्म किया था। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का संयुक्त खिताब जीता। 2003 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई और 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी अपने नाम की। लॉर्ड्स के मैदान पर नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद बालकनी में शर्ट लहराकर मनाया गया गांगुली का जश्न भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित पलों में गिना जाता है। यही ऐतिहासिक दृश्य उनकी बायोपिक के फर्स्ट-लुक पोस्टर का मुख्य आकर्षण भी है।

अंबेडकर कालेज में नशा उन्मूलन अभियान का हुआ आयोजन

बैतूल। शहर के प्रसिद्ध कालेज भीमराव रामराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय, बैतूल में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के आदेशानुसार ' 'नशे से दूरी, है जरूरी 2.0 अभियान '' के अंतर्गत नशा मुक्ति गतिविधियों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के विशाल सभागार में नशे के प्रति जन जागरूकता के विभिन्न रचनात्मक कार्यकम, शार्ट फिल्म का प्रदर्शन कर यह आयोजन किया गया तथा यह सुनिश्चित करवाया गया कि महाविद्यालय के आसपास तम्बाकू, सिगरेट की कोई गुमठी या दुकान संचालित न हो एवं शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के संचालक इंजीनियर ध्रुवप्रकाश अग्रवाल मौजूद रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ जी.डी. देशमुख द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में बडी संख्या मे कालेज के बी.एड. स्कालर्स एव बी.एड. का स्टाफ मौजूद रहा।

यार्ड रीमॉडलिंग से दो प्रमुख ट्रेनों का बदला मार्ग

20 जुलाई तक भोपाल–बीना–झांसी रूट प्रभावित

बैतूल। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। इस कार्य के कारण दो महत्वपूर्ण ट्रेनों, हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, के संचालन मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जानकारी के अनुसार, ट्रेन क्रमांक 12721 हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का मार्ग 20 जुलाई 2026 तक बदला गया है। यह ट्रेन अब अपने नियमित मार्ग भोपाल-बीना-झांसी के बजाय भोपाल-संत हिरदाराम नगर-नागदा-कोटा-मथुरा जंक्शन होकर चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन क्रमांक 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का मार्ग भी 19 जुलाई 2026 तक परिवर्तित रहेगा। यह ट्रेन झांसी-बीना-भोपाल के बजाय मथुरा-कोटा-नागदा-भोपाल मार्ग से संचालित होगी। नागपुर रेल मंडल के बैतूल, आमला, मुलताई और इटारसी सेक्शन के यात्रियों के लिए हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस एक लोकप्रिय लंबी दूरी की ट्रेन मानी जाती है। बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन से भोपाल, झांसी, दिल्ली और हैदराबाद की यात्रा करते हैं। मार्ग परिवर्तन के कारण इन यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी।

बैतूल में संगठन सृजन अभियान के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ

बैतूल। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को बैतूल में ब्लॉक अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों एवं मंडलम अध्यक्षों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्देश्य संगठन को अधिक सशक्त, सक्रिय और प्रभावी बनाना है। प्रशिक्षण शिविर में प्रभारी प्रशिक्षक महेंद्र जोशी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट, प्रशिक्षक चिराग परमार तथा कनेक्ट सेंटर प्रभारी भूपेंद्र पूरावत ने संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं की को भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। वक्ताओं ने कहा कि सशक्त संगठन ही जनसेवा और जनविश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच सक्रिय रहने और कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सचिव समीर खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा सहित जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

इंजीनियर के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश, बटकीडोह हाईस्कूल में विद्यार्थियों से किया संवाद

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम बटकीडोह का भ्रमण कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं शासकीय हाई स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कमियां पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को दिए। कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिले के सभी प्रगतिरत, अपूर्ण एवं हैंडओवर किए जा चुके आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर डॉ सोनवणे ने शासकीय हाई स्कूल बटकीडोह का निरीक्षण कर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों की रुचि, भविष्य की योजनाओं और करियर संबंधी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 10 दिनों के भीतर जिले के सभी स्कूलों में करियर ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों की सही जानकारी मिल सके। साथ ही विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल गतिविधियां भी नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में जो भी क्षेत्र चुने चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चित्रकार, खिलाड़ी या कोई अन्य क्षेत्र उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य अभी से निर्धारित करें और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत एवं समर्पण के साथ प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन एवं शैक्षणिक वातावरण के लिए शिक्षक एम.के. दास की सराहना करते हुए कहा कि एक अच्छा शिक्षक पूरे विद्यालय की दिशा बदल सकता है। उन्होंने विद्यालय के समग्र विकास के लिए हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने स्मार्ट क्लास के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का सब्सक्रिप्शन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने यहां ग्रामीणों की मांग पर बिजली के लिए खंभे, पेयजल के लिए कुआं और आंगनवाड़ी भवन के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए।

सड़क चौड़ीकरण में बाधा बना दो मंजिला मकान ढहाया

बैतूल। इंदिरा वार्ड में शुक्रवार को नगर पालिका ने सड़क निर्माण के लिए पक्के अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एक दो मंजिला मकान के अतिक्रमित हिस्से को जेसीबी और ड्रिल मशीन की मदद से तोड़ा गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा रही और पुलिस बल भी तैनात था। नगर पालिका के अनुसार, इटारसी रोड स्थित सतपाल आश्रम के सामने से गुजरने वाली सड़क को साढ़े सात मीटर चौड़ा किया जाना है। इसी सड़क के निर्माण में बाधा बन रहे पक्के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। शुक्रवार को महिला दीप मालिक के दो मंजिला मकान का करीब 10 फीट हिस्सा जेसीबी की मदद से ढहाया गया। मकान का पिछला हिस्सा प्रस्तावित सड़क की सीमा में आ रहा था। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि संबंधित परिवार को पहले कई बार नोटिस दिए गए थे। अंतिम बार 72 घंटे का समय भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पालिका को यह कार्रवाई करनी पड़ी। मकान दो मंजिला होने के कारण केवल जेसीबी से काम संभव नहीं था, इसलिए ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई का नेतृत्व राजस्व निरीक्षक (आरआई) मदन विनोदकर और बीएल परते ने किया। उन्होंने बताया कि सड़क की निर्धारित चौड़ाई के अनुसार अतिक्रमण हटाना आवश्यक था, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए।

कक्ष निर्माण में देरी पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को नोटिस

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम हीरापुर का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान ग्रामीण सविता सोनी ने आवास एवं आजीविका से जुड़ी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की जांच कर लाभ दिलाने तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोडने़ के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम में संचालित किए जाने वाले रेशम केंद्र के संचालन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम में नल-जल योजना बंद होने की शिकायत पर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को

तत्काल टीम भेजकर जल स्रोत एवं पाइपलाइन की जांच कर शीघ्र समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा रखी गई मार्ग निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान सहित अन्य समस्याओं पर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत भवन के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए।

अतिरिक्त कक्ष निर्माण में देरी पर कार्रवाई– कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने ग्राम हीरापुर की प्राथमिक शाला का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर दर्ज छात्र संख्या की जानकारी ली तथा शिक्षकों को पर्याप्त रोशनी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए शाला का सुव्यवस्थित संचालन करने और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्ष का भी अवलोकन किया। निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्यान्ह भोजन कक्ष का निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से तैयार किए जा रहे भोजन की जानकारी ली तथा निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश– कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हीरापुर का भी निरीक्षण किया। ग्रामीणों द्वारा चिकित्सक नहीं होने की शिकायत पर बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. पवित्र कुमार मिस्त्री की पदस्थापना हो चुकी है और उन्होंने गत दिवस कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्टर ने नवपदस्थ चिकित्सक को पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नियमित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव सेवाओं, मलेरिया एवं डेंगू के प्रकरणों की जानकारी ली तथा आवश्यक दवाओं के उपलब्ध स्टॉक का भी निरीक्षण किया।

एमपी में मोबाइल गवर्नेंस एवं विकास विषय पर पुस्तक प्रकाशित

भोपाल। इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ललित कुमार की नवीन पुस्तक 'मोबाइल गवर्नेंस एवं विकास' प्रकाशित हो गई है। यह पुस्तक मध्यप्रदेश में मोबाइल गवर्नेंस, डिजिटल प्रशासन तथा विकास के विभिन्न आयामों पर आधारित एक महत्वपूर्ण अकादमिक कृति है।

पुस्तक में डिजिटल मध्यप्रदेश, ई-गवर्नेंस, मोबाइल आधारित सरकारी सेवाओं, ग्रामीण विकास, नागरिक सहभागिता तथा सुशासन में मोबाइल प्रौद्योगिकी की भूमिका का शोधपरक एवं व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक पत्रकारिता एवं जनसंचार, लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी संदर्भ ग्रंथ सिद्ध होगी।

इस अवसर पर डॉ. ललित कुमार ने कहा आज मोबाइल गवर्नेंस शासन और नागरिकों के बीच संवाद एवं सेवा वितरण का प्रभावी माध्यम बन चुका है। यह पुस्तक मध्यप्रदेश में डिजिटल युग में विकास और सुशासन की बदलती अवधारणाओं को समझने का एक सार्थक प्रयास है। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के डीन डॉ. राजेश शर्मा ने कहा, डॉ. ललित कुमार की यह पुस्तक समकालीन विषय पर आधारित एक उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान है। यह विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी तथा डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करेगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकों एवं शिक्षकों ने डॉ. ललित कुमार को पुस्तक प्रकाशन पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल शैक्षणिक एवं शोध कार्यों की निरंतर सफलता की कामना की।

नौ राज्यों के युवाओं ने एक स्वर में पढ़ी कविता - 'कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती'

कला समीक्षक विनय उपाध्याय ने बताया शब्द और ध्वनि का महत्व

भोपाल। हीनता और दीनता की नहीं, हिन्दी प्रभुता की भाषा है। बदलती तकनीक और माध्यमों ने आज हिन्दी के साथ नए कौशल की सुनहरी संभावनाओं का जो संसार रचा है, वह अभूतपूर्व है। कहने और सुनने की आपसदारी में साहित्य की विरासत और रचनात्मकता दोनों के प्रति रूचि तथा जिज्ञासा बढ़ी है। युवा पाठक आज कबीर, निराला,महादेवी, दिनकर, दुष्यंत, भवानीप्रसाद मिश्र, और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे कवियों को केवल पढ़ ही नहीं रहे, उन्हें अपनी धुनों में गा भी रहे हैं।

सुप्रसिद्ध कला समीक्षक तथा लेखक विनय उपाध्याय इन सकारात्मक विचारों के साथ नौ राज्यों के छात्र - छात्राओं के बीच प्रस्तुत हुए। असम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा प्रदेशों के चलीस से भी अधिक युवाओं से संवाद करते हुए विनय ने कहा कि हिन्दी की कहानी भारतीय भाषाओं और बोलियों के संयोग की कहानी है। यह परस्परता ही उसकी बहुरंगी तासीर है। विनय ने स्वर और व्यंजनों के तालमेल से शब्द और भाषा के अविष्कार की रोचक व्याख्या की। इस तारतम्य में उन्होंने अलग - अलग कालखंडों में रची गयी कविताओं का उदाहरण दिया। माहौल तब गमक उठा जब सभी छात्र- छात्राओं ने सामूहिक स्वरों में लोकप्रिय हिन्दी कविता ' कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती' का पाठ लिया।

गौरतलब है कि भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की पहल पर छात्र अध्ययन यात्रा के तहत युवाओं का दल रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय तथा विश्वरंग फाउण्डेशन के संयोजन में हिन्दी के प्रयोगों का सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है । टैगोर विश्वकला एवं संस्कृति केंद्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने 'ध्वनि, शब्द, स्वर, संवेदना और विचार के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी भाषा नौ रसों को आत्मसात कर एक निश्छल नदी की भाँति गतिमान है। हिंदी ने अपने द्वार सदैव सभी भाषाओं के लिए खुले रखें हैं। सभी भाषाओं और बोलियों से वह रस ग्रहण कर विकसित और निरंतर विस्तारित होती रही है। हिंदी में ध्वनि, शब्द, स्वर, संवेदना और विचार का ताना बाना ही अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है।

इस अवसर पर युवा कवि मुदित श्रीवास्तव ने कविता लेखन के सत्र में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि युवाओं को विचारशील होना चाहिए और सतत रूप से रचनात्मक विचारों की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। आज के समय में युवाओं का संवेदनशील होना भी नितांत जरूरी है। हमारे सोचने में, हमारे कार्यों में हमारे लेखन में संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी है। बगैर संवेदनाओं के कुछ भी सोचना, कुछ भी लिखना निरर्थक है ।

'नीलांचल वाले तू न संभाले तो कौन संभाले'

नगर के इतिहास में पहली बार मिश्रजी मंदिर से जगन्नाथ यात्रा निकली, यात्रा प्रारंभ होते बरसात ने किया स्वागत

सोहागपुर। नगर के इतिहास में पहली बार मिश्रजी मंदिर से सारदा सेवा संघ के तत्वावधान में जगन्नाथ यात्रा निकाली गई।यह भी संयोग रहा कि जगन्नाथ यात्रा निकलते ही पानी बरसने लगा। विगत कई दिनों से गर्मी की तपन ने सोहागपुर के नगरवासियों को हलाकान कर दिया था।इस बरसात से नागरिकों को राहत महसूस हुई। जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व विख्यात मिश्र जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। जगन्नाथ रथयात्रा को खींचने में नगर के नागरिक के अलावा मातृशक्ति भी पीछे नहीं रही। इन्द्र कुमार दीवान के साथ ढोलकों की टोली ने रथयात्रा की शोभा बढ़ा दिया। इसी क्रम में अधिकांश नागरिक पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वहीं भारी संख्या में मातृशक्ति भी पीले एवं लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वहीं काफी मातृशक्ति पगड़ी पहने हुए थी।रथयात्रा में नागरिक उद्घोष कर रहे थे।जय जगन्नाथ,जय जगन्नाथ नीलांचल वाले तू न संभाले तो कौन संभाले ,मेरी नैया है अब तेरे हवाले आदि। वहीं स्कूली बच्चे भी इस रथयात्रा में पीछे नहीं रहे। रथयात्रा में कई नागरिक एवं मातृशक्ति सड़क साफ करती भी नजर आई। इसी रथयात्रा में मातृशक्ति नृत्य भी कर रही थी। वहीं दीवान मंदिर प्रबधक इन्द्र कुमार दीवान हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में परमात्मा के स्नेह में

झूमकर आनंदित होते हैं। इसी क्रम आज ब्रह्मलीन पंडित मनमोहन मुद्गल की झलक उनके ज्येष्ठ पुत्र पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल में देखने को मिली। जिसमें भगवान् जगन्नाथ प्रभु के रंग रंगकर झूमने लगे। इससे नागरिकों का मन आनंदित हो गया।रथयात्रा बिहारी चौक, कन्या शाला, पुराने थाने,मुख्य बाजार, कमानिया गेट,मातापुरा आदि स्थानों से होकर रामगंज में राम जानकी मंदिर में रथयात्रा पहुंची।यह भी पूजा-अर्चना की गई। रथयात्रा पुनः बिहारी चौक मिश्र जी मंदिर पहुंची। इस नगर की प्रथम जगन्नाथ यात्रा में, क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह, पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल,नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष, कृष्णा पालीवाल,दीवान मंदिर प्रबधक इन्द्र कुमार दीवान,,पूर्व नपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सुश्री राजो मालवीय, समाजसेवी कन्नू लाल अग्रवाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल,जनपद उपाध्यक्ष राघवेंद्रसिंह पटेल, कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल , पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, जीवन जी दुबे, समाजसेवी विशाल गोलानी, हेमकुमार दीवान हिंमू दीवान, ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनी सरोज, समाजसेवी संजय खंडेलवाल,यश खंडेलवाल ,नीरज चौधरी, जगदीश भावसार, पूर्व नपाध्यक्ष शशि मालवीय, शरद चौरसिया, वकील प्रांजल तिवारी,गोलू अग्रवाल, पार्षद भास्कर मांझी, पीयूष पालीवाल, मनोज अग्रवाल, विक्रम रघुवंशी सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थीं।

क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने कन्या शाला में किया साइकिल वितरण

सोहागपुर। क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने पीएम श्री कन्या शाला परिसर में करीबन 61.73 लाख रुपए की लागत से बने 5 अतिरिक्त कक्षों का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, पार्षद गौरव पालीवाल,गोलू अग्रवाल के अलावा जनप्रतिनिधि एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा शिक्षक गण उपस्थित थे। इसी अवसर पर विधायक विजयपालसिंह ने करीबन 25 छात्राओं को

साइकिलें प्रदान की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है । छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज छात्राओं को साइकिल प्राप्त होने पर खुशी की झलक अलग ही दिखाई दे रही है । विद्यालय अतिरिक्त कक्षों से छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध हों रही है। इससे निश्चित ही छात्राओं शिक्षा प्राप्त होने का नवीन अनुभव मिलेगा। इसी अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इसके पूर्व क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने सोहागपुर विधानसभा के माखन नगर एवं ग्राम सेमरी हरचंद में भी छात्र छात्राओं को साइकिलों का विवरण किया।

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सहकारी बैंक समितियों एवं सीएससी की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

रायसेन (निप्र)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा कराने हेतु प्रेरित करने के लिए बुधवार को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में जिला स्तरीय सहकारी बैंक समितियों एवं सीएससी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिला सहकारी बैंक के सीईओ श्री अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी, जिले के सभी वीएलई एवं पैक्स प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में सीईओ श्री अजय कुमार ने कहा कि अल-नीनो के संभावित प्रभाव से अनियमित वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को देखते हुए किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जाए। किसानों को बताएं कि फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं मौसम के कारण होने वाले अन्य जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने सभी वीएलई एवं पैक्स प्रतिनिधियों से कहा कि किसानों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने हेतु 31 जुलाई 2026 के पहले ही पंजीयन सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की ओर से श्री विनय यादव ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नामांकन प्रक्रिया, पंजीयन की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

सीहोर वृत्त में अभी तक लगाए गए 81,147 स्मार्ट मीटर

संपर्क अभियान के शिविरों में बताया जा रहा स्मार्ट मीटर का डेमो

सीहोर (निप्र)। बिजली कंपनी द्वारा सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सीहोर के उप महाप्रबंधक ने बताया कि सीहोर वृत में 1,28,112 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 81,147 मीटर लगाए जा चुके हैं। इसी प्रकार डीटीआर पर 7404 स्मार्ट मीटर का लक्ष्य है, जिसमें से 2671 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कंपनी द्वारा संपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में भी स्मार्ट मीटर्स का डेमो दिया जा रहा है स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर एंव लोड मॅनेजमेंट का लाइव डेमो दिखाया जा और मीटर रीडिंग संबंधी भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि मीटर का इनपुट एंव आउटपुट लोड कैसे संतुलित रहता है उप महाप्रबंधक ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है ऊर्जा की खपत को ट्रैक कर नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है टाइम आफ डे खपत पर सीहोर संभाग में उपभोक्ताओं को 25,42,161 रूपये की छूट प्रदान की गई है। स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नही होती है। स्मार्ट मीटर लगाने से रीडिंग कार्य में भी पारदर्शिता आई है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही है। एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते है।

अब स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में विद्यार्थी 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश

उच्च शिक्षा विभाग ने द्वितीय चरण की कॉलेज लेवल काउंसलिंग की बढ़ाई तिथि

हरदा (निप्र)। उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वितीय चरण की कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे।इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा ने मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण की सीएलसी की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी शर्तें, नियम एवं दिशा निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।

■ सूक्ष्म उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं युवा : कलेक्टर

संरक्षित खेती एवं जल संरक्षण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें किसान

■ उद्यानिकी योजनाओं का किया जाए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार

▶▶ कलेक्टर ने उद्यानिकी एवं पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसल इकाइयों का किया निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने ग्राम खामलिया, चैनपुरा और बिलकिसगंज में उद्यानिकी विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया और किसानों एवं हितग्राहियों से चर्चा कर विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम खामलिया में किसान श्री मिठूलाल मेवाड़ा के द्वारा पॉली लाइनिंग फार्म पॉण्ड और शेडनेट हाउस में की जा रही खीरा की खेती तथा बैंगन की फसल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही किसान द्वारा प्याज भंडार गृह में सुरक्षित भंडारित प्याज का भी अवलोकन किया। उन्होंने किसान द्वारा की गई वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्था की सराहना करते हुए किसानों को फसल कटाई उपरांत प्रबंधन एवं भंडारण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संरक्षित खेती एवं जल संरक्षण के इन नवाचारों की सराहना करते हुए किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर ने ग्राम चैनपुरा में किसान श्री श्याम सुंदर वर्मा के पॉलीहाउस का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पॉलीहाउस के अंदर उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब के फूलों की खेती का अवलोकन किया तथा संरक्षित खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की प्रशंसा की। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाए तथा कृषि एवं उद्यानिकी आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही उद्यानिकी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। उन्होने कहा कि फील्ड अमला किसानों को मत्स्य एवं उद्यानिकी की खेती के लिए प्रेरित करें और उन्हें सहयोग करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हितग्राही छोटे-छोटे उद्योग या प्रसंस्करण इकाई लगाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं और इससे अतिरिक्ति रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकते हैं।

कलेक्टर ने ग्राम बिलकिसगंज में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लाभान्वित इकाई 'सोमेश नमकीन' का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं विपणन व्यवस्था का अवलोकन किया तथा उद्यमी से चर्चा कर व्यवसाय के विस्तार एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री जगदीश सिंह मुझाल्दा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

आचार्यश्री समय सागर ने मांस निर्यात पर जताई चिंता

नर्मदापुरम (निप्र)। जैन धर्म के महान तपस्वी संयम, सत्य और अहिंसा के प्रतीक, आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य आचार्य 108 समय सागर महाराज का बुधवार सुबह नर्मदापुरम शहर में आगमन हुआ। रसूलिया डबल फाटक पर आचार्य श्री के साथ 20 पिच्छी मुनिराजों का शहर में मंगल प्रवेश हुआ।

जहां सकल जैन समाज और शहरवासियों ने आचार्य श्री का स्वागत किया। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उनके स्वागत में जगह-जगह टेंट, बैंड-बाजे और रंगोलियां बनाकर शहर को सजाया गया। आचार्य श्री रसूलिया, भोपाल तिराहा, एनएमवी तिराहा, सतरस्ते होते हुए बड़े दिगंबर जैन मंदिर, मंगलवारा पहुंचे। यहां आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन, पूजन-अर्चना के बाद प्रवचन हुए। जिसमें उन्होंने अहिंसा की सीख दी। भारत से हो रहे मांस निर्यात पर चिंता जताई।

प्रवचन की मुख्य बातें : आचार्य समय सागर महाराज ने कहा कि ट्ठ 'सांसारिक प्राणी स्वार्थी है। अपने जीवन को सुख-शांति से बनाने के लिए दूरदृष्टि रखता है, लेकिन परमार्थ उसके जीवन में हाथ नहीं रख सकता।' उन्होंने बड़े-बड़े हिंसात्मक कार्यों पर चिंता जताते हुए कहा कि ट्ठ 'सुना है भारत से मांस निर्यात होता है। इसे बंद करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन आज भी यह कार्य चल रहा है और हम देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं।'

महाराज ने कहा ट्ठ 'मानव के लिए तो बहुत प्रबंध होते हैं, वो सुख-सुविधा से जीता है। थोड़ी प्रतिकूलता आने पर प्रतिकार करता है। लेकिन पशु-पक्षियों के जीवन के लिए हमारी सकारात्मक दृष्टि नहीं है।

शारदा स्व-सहायता समूह की महिलाएं बनीं आत्मनिर्भरता की पहचान

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले की इछावर तहसील के छोटे-से गांव पटारिया सीधा में कभी आर्थिक तंगी, सीमित संसाधनों और रोजगार के अभाव से जूझने वाली इस गांव की महिलाओं ने आज अपनी मेहनत, एकजुटता और आत्मविश्वास के दम पर सफलता की नई कहानी लिखी है। इस परिवर्तन के केंद्र में है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत गठित शारदा स्व-सहायता समूह, जिसने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनके जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और नई पहचान भी स्थापित की। शारदा स्व-सहायता समूह की शुरुआत उन महिलाओं ने की थी, जिनके सामने आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं था। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही थीं।

एनआरएलएम के माध्यम से समूह का गठन हुआ, जहां महिलाओं ने नियमित बचत, बैंकिंग व्यवस्था और स्वरोजगार की बुनियादी जानकारी हासिल की। छोटी-छोटी बचत से शुरू हुई यह यात्रा धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता के मजबूत इरादे में बदल गई। समूह की प्रगति में निर्णायक मोड़ तब आया, जब उसका जुड़ाव मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, धमांडा शाखा से हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक सखी श्रीमती अनीता बामनिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली, खाता संचालन, ऋण प्रक्रिया और समय पर ऋण चुकाने के महत्व से परिचित कराया। उनके मार्गदर्शन में समूह को सबसे पहले 1.50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। समूह की महिलाओं ने इस राशि का उपयोग बकरी पालन, किराना दुकान, सब्जी विक्रय जैसे छोटे-छोटे स्वरोजगार शुरू करने में किया। मेहनत और ईमानदारी के साथ व्यवसाय संचालित करते हुए उन्होंने समय पर पूरा ऋण चुकाया और बैंक का भरोसा जीत लिया। पहली सफलता ने महिलाओं का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। उनकी कार्यशैली और वित्तीय अनुशासन को देखते हुए बैंक ने समूह को 3 लाख रुपये का दूसरा ऋण स्वीकृत किया। इस बार महिलाओं ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। किसी ने डेयरी व्यवसाय शुरू किया, तो किसी ने सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को अपनाया। उनकी निरंतर प्रगति और समय पर ऋण पुनर्भुगतान ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। परिणामस्वरूप समूह को क्रमशः 6 लाख रुपये और फिर 10 लाख रुपये तक का ऋण भी प्राप्त हुआ। इस पूरी यात्रा में बैंक सखी अनीता बामनिया केवल बैंक और समूह के बीच की कड़ी नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने एक मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाई। उनके सतत सहयोग से महिलाओं ने वित्तीय निर्णय लेना सीखा, बैंकिंग व्यवस्था को समझा और आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। आज शारदा स्व-सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं। उनके परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और जीवन स्तर पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हुआ है। गांव में महिलाओं की पहचान अब केवल गृहिणी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सफल उद्यमी, परिवार की आर्थिक आधारशिला और समाज में निर्णय लेने वाली सशक्त महिलाएं बन चुकी हैं। शारदा स्व-सहायता समूह से प्रेरणा लेकर अन्य महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ रही हैं और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।

यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब सामूहिक प्रयास, सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एक साथ जुड़ते हैं, तो बदलाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल देता है। शारदा स्व-सहायता समूह की सफलता यह संदेश देती है कि यदि महिलाओं को अवसर, विश्वास और सही मार्गदर्शन मिले, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास की मजबूत आधारशिला बन सकती हैं।

"प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना" के तहत रसोईया सह सहायक का होगा ईकेवायसी सत्यापन

हरदा (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमती अंजली जोसेफ की अध्यक्षता मे बुधवार को पीएम पोषण कार्यक्रम की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में भोजन की गुणवत्ता, शालाओं के सुचारू क्रियान्वयन तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कढ़े निर्देश दिये गए। विकासखंड हरदा में माह जून 2026 में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई एवं उपस्थिति बढ़ाने हेतु सख्त निर्देश दिये गए।

बैठक में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पीएम पोषण कार्य से संलग्न सभी रसोईयों का शत्-प्रतिशत ईकेवायसी का कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये गए। साथ ही कार्यक्रम की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए डीपीसी, बीआरसी, बीएसी एवं जनशिक्षक को ऑनलाईन निरीक्षण के निर्देश दिये गए। मां की बगिया का निर्माण तथा रखरखाव किये जाने एवं लोकोस पोर्टल पर स्व-सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन शत-प्रतिशत किये जाने हेतु कहा गया। बैठक में निर्देशित किया गया कि शाला में दर्ज सभी विद्यार्थियों का एवं पीएम पोषण कार्य से संलग्न रसोईयों का प्रतिमाह स्वास्थ्य परीक्षण किया जावे तथा इसकी विकासखंडवार जानकारी प्रस्तुत की जावे ।

आगामी बैठक में स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये गए। स्वच्छता की दृष्टि से पीने के पानी टंकी की नियमित सफाई कराने के भी निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमती अंजली जोसेफ द्वारा निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जायेगा। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सभी गर्भवती महिलाओं का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर क्षेत्र का भ्रमण कर सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित करें। साथ ही उनकी 4 जांचें अनिवार्य रूप से कराएं। उच्च जोखिम वाली महिलाओं का उचित मेनेजमेन्ट करें तथा हर गर्भवती महिला का फॉलोअप लें। उन्होने निर्देशित किया कि भ्रमण के दौरान चिन्हांकित कुपोषित व अतिकुपोषित श्रेणी के बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में अनिवार्य रूप से भर्ती कराएं। सभी बीएमओ जूम मिटिंग के माध्यम से प्रत्येक तीन से चार दिवस में यूवीन एवं एचआईएमएस का डाटा कलेक्शन की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विवेक शर्मा सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और अस्पतालों में दवाओं एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' का जिले में शुभारंभ

नशे के खिलाफ जिले में 30 जुलाई तक चलेगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान

बैतूल (निप्र)। जिले में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' का औपचारिक शुभारंभ 15 जुलाई को पुलिस परेड ग्राउंड से किया गया। इस अवसर पर यहां से जागरूकता रैली एवं ड्रग अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया।

पुलिस अधिक श्री वीरेंद्र जैन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली प्रमुख मार्गो से होते वापस पुलिस ग्राउंड पहुंची। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने कहा कि नशा व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है।

युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। एसपी श्री जैन ने बताया कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक जिलेभर में प्रतिदिन जागरूकता रैलियां, पंपलेट वितरण, नुक्कड़ सभाएं, बैनर-पोस्टर, शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन और अन्य जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही नशे के चिन्हित स्थलों पर पहुंचकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा युवाओं और अभिभावकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ एडिशनल एसपी श्री कमलेश कुमार खरपुसे, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सुश्री रोशनी वर्मा, एसडीओपी बैतूल अन्नपूर्णा सिरसाम, डीएसपी शेफा हाशमी सहित अन्य विभागीय अधिकारी, पुलिसकर्मी, स्कूल-कॉलेज के विधार्थी, खिलाड़ी उपस्थित रहे।

कार्यक्रमों की रूपरेखा

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खेल एवं युवा कल्याण विभाग , सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका सहित अन्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं एनजीओ एवं ग्राम रक्षा समितियां 30 जुलाई तक नशे के विरुद्ध जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेगी। अभियान के तहत 16 जुलाई को स्कूल-कॉलेजों में रील, शॉर्ट फिल्म सहित जनजागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ का आयोजन होगा। वहीं 17 जुलाई को व्याख्यान, लघु फिल्म प्रदर्शन तथा स्कूलों के आसपास तंबाकू-सिगरेट की गुमठियां नहीं होने का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही 18 जुलाई को झुग्गी-झोपड़ी एवं चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, नशा पीड़ितों और उनके परिजनों को पुनर्वास केंद्रों की जानकारी तथा चिकित्सीय परामर्श दिया जाएगा तथा 19 जुलाई को ऑटो एवं शासकीय वाहनों पर पोस्टर, सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।

इसी प्रकार 20 जुलाई को मानव श्रृंखला बनाकर जनजागरूकता कार्यक्रम होगा तथा 21 जुलाई को चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता, अभिभावकों की सहभागिता होगी। वहीं 22 जुलाई को गणमान्य व्यक्तियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के रिकॉर्डेड संदेशों का प्रचार-प्रसार तथा नशा छोड़ चुके लोगों की प्रेरक कहानियों का सोशल मीडिया पर प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा 23 जुलाई को बसों, सार्वजनिक परिवहन एवं नगर निकाय की एलईडी स्क्रीन पर जागरूकता फिल्म एवं संदेशों का प्रसारण होगा तथा 24 जुलाई को पुलिस थाना परिसरों में ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी प्रकार 25 जुलाई को महिला एवं बाल विकास विभाग के शौर्य दल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं तथा ग्राम-नगर सुरक्षा समितियों की सहभागिता से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा तथा 26 जुलाई को व्यापारियों, एनजीओ और सोशल ग्रुप के सहयोग से बाजार, हाट एवं सार्वजनिक स्थलों पर नशा विरोधी जनसंवाद।

27 जुलाई को शासकीय-अशासकीय छात्रावास, धार्मिक संस्थानों, फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 28 जुलाई को वन, सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से विशेष जनजागरूकता अभियान आयोजित होगा। इसके अलावा 29 जुलाई को स्थानीय खेल प्रशिक्षकों के सहयोग से खिलाड़ियों के बीच नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम तथा 30 जुलाई को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समापन समारोह, जिसमें ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

दतिया उपचुनाव से पहले एक तस्वीर से खलबली

वंदे भारत में साथ दिखे बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी

भोपाल। दतिया विधानसभा उपचुनाव की बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच शुक्रवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौर में भी लोकतांत्रिक सौहार्द्र और मर्यादा का बेहतरीन संदेश दिया। दतिया जाते समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आमने-सामने की सीट पर बैठकर खुशनुमा माहौल में बातचीत करते नजर आए। उनके साथ राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी सफर कर रहे थे। चुनावी मौसम में दो धुर विरोधी दलों के सेनापतियों का इस तरह सहज वातावरण में सफर करना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।

दोनों ने जतायी अपनी-अपनी जीत की उम्मीद

इस दिलचस्प सफर के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच दतिया उपचुनाव और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर लंबी चर्चा हुई। हालांकि, चुनावी बातचीत में दोनों ने अपनी-अपनी पार्टी के जीतने का पूरा भरोसा जताया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटकर दावा किया कि दतिया की जनता का झुकाव भाजपा की तरफ है और पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ही यहां से जीत का परचम लहराएंगे। ट्रेन के इस सौहार्द्रपूर्ण माहौल के इतर दतिया की जमीन पर आज दोनों ही दल अपने-अपने चुनाव अभियान को चरम पर ले जाने की तैयारी में हैं।

सीएम ने दिल्ली में की निवेशकों के साथ दो बैठकें

एमपी को मिले 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

कहा-27 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

भोपाल। दिल्ली में आयोजित 'भारत टेक्स-2026' और 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में एमपी को रोजगार की दिशा में बड़ा आश्वासन मिला है। इन दोनों बड़े आयोजनों के माध्यम से मप्र को कुल रू. 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे प्रदेश में लगभग 27,592 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली के होटल द लीला पैलेस में देश-विदेश के उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने मध्यप्रदेश को देश का उभरता हुआ औद्योगिक एवं टेक्सटाइल हब बताते हुए कहा कि राज्य निवेशकों के लिए नीति, नीयत, प्रतिभा, प्रवृत्ति, सुविधा, सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह, सेवा और सुरक्षा की 10 गारंटियां लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (GIS-2027) में भाग लेने का विशेष आमंत्रण दिया और उन्हें अनुकूल नीतियों तथा त्वरित प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया।

वस्त्र और परिधान क्षेत्र में 1,592 करोड़ का निवेश- भारत मंडपम में आयोजित टेक्सटाइल राउंडटेबल के दौरान मध्यप्रदेश के वस्त्र उद्योग को एक नई दिशा मिली। इस सत्र में प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र, कौशल विकास और निर्यात संवर्धन पर गहन मंथन हुआ। इस विशेष आयोजन के माध्यम से प्रदेश को वस्त्र क्षेत्र में 1,592 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में लगभग 15,700 रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कई देशों के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन बैठक- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार विस्तार के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न देशों के मंत्रियों और राजनयिकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। श्रीलंका के उद्योग मंत्री सुनील हंदुन्नेत्ती और ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स के साथ कृषि, जैव ईंधन, खनन और एयरोस्पेस पर सार्थक चर्चा हुई। वहीं रूसी वित्तीय प्रतिनिधिमंडल, इटली और फ्रांस के प्रतिनिधियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी।

रक्षा, डेटा सेंटर और भारी उद्योगों में 18,601 करोड़ का निवेश

दिल्ली निवेश संवाद में अत्याधुनिक और रणनीतिक क्षेत्रों में भारी निवेश के प्रस्ताव आए हैं। रक्षा, डेटा सेंटर, ट्रांसफॉर्मर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल उत्पाद और खिलौना उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को रू. 18,601 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से लगभग 11,892 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें ब्रह्मास्त्र एक्सप्लोसिव, सीमेंस एनर्जी, सिटाक रे, सनब्रिज डिफेन्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस और वीरा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं।

वैश्विक व्यापार और निर्यात बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण एमओयू

मप्र में व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एमपीआईडीसी ने सात महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स और एसोचैम के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जबकि अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के साथ हुए समझौते से प्रदेश के छोटे उद्योगों और शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न अपैरल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काउंसिल्स के साथ मिलकर वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने और बायर-सेलर मीट आयोजित करने पर भी समझौता हुआ।

विक्रमोत्सव 2026 को मिला बीटा गोल्ड अवॉर्ड

भोपाल। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष तीसरा राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री द्वारा 15 एवं 16 जुलाई को देहरादून में आयोजित हिन्दुस्तान 2.0 नेशनल चिंतन शिविर एवं एक्स्पो में विक्रमोत्सव 2026 को BITA Awards 2026 अंतर्गत Government Event of the Year (Gold Award) का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। बीटा की टीम भोपाल आकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यह सम्मान प्रदान करेगी। विक्रमोत्सव दुनिया का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला सांस्कृतिक आयोजन है। जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बिजनेस इवेंट भी शामिल है। इसके पहले भी नई दिल्ली में 2-3 मई 2026 को आयोजित शो ऑफ इंडिया कांक्लेव 2026 में विक्रमोत्सव 2026 को सांस्कृतिक लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड तथा लाइव इवेंट में सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता में सिल्वर अवार्ड मिल चुका है।

सीएम डॉ.यादव के नेतृत्व में मिल रही नई ऊंचाई: मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ही दूरदर्शी पहल पर उज्जैन में विक्रमोत्सव को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है जो आज पूरे देश में फैल रहा है ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विक्रमोत्सव 2026 को प्राप्त यह तीसरा राष्ट्रीय सम्मान मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उत्कृष्ट आयोजन क्षमता और जनभागीदारी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकृति है। यह उपलब्धि हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी तथा भविष्य में मध्यप्रदेश को सांस्कृतिक क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मिल चुके हैं तीन सम्मान: विक्रमोत्सव दुनिया का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला सांस्कृतिक आयोजन है। इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बिजनेस इवेंट भी शामिल है। इसके पहले विक्रमोत्सव : 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा लांगस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। 'वाउ' अवार्ड एशिया-2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड मिल चुका है। वर्ष-2024 में विक्रमोत्सव को एशिया का 'बिगेस्ट रिलीजियस' अवॉर्ड मिला था।

17.72 करोड़ से अधिक लोग जुड़े: विक्रमोत्सव 2026 के दौरान आयोजन के प्रसारण ने डिजिटल आउटरीच और कम्युनिटी एंगेजमेंट के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 7 फरवरी से 24 मार्च 2026 के बीच आयोजन से संबंधित गतिविधियों ने कुल 17.72 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई।

90 घोड़ों की मौत के बाद जबलपुर शिफ्ट हुए थे बेज़ुबान

केयरटेकर ने कहा-सब बेच दिए,हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

भोपाल। हैदराबाद से जबलपुर के पनागर लाए गए रेस के घोड़ों की संदिग्ध मौतों और उन्हें गायब करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को पनागर थाना प्रभारी और जिला पशु अधिकारी के साथ रैपुरा स्थित फार्म हाउस में जाकर घोड़ों की लाइव स्थिति की जांच करने की अनुमति दे दी है। इस जांच टीम के साथ वेटरनरी डॉक्टरों का एक विशेष दल भी मौजूद रहेगा। यह आदेश जबलपुर निवासी पशु प्रेमी सिमरन इस्सर की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें केयरटेकर द्वारा कोर्ट में दिए गए उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई गई, जिसमें उसने कहा था कि उसने बचे हुए सभी घोड़ों को बेच दिया है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि केयरटेकर को इन घोड़ों को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

क्या है घोड़ों की मौत का पूरा नेक्सस- याचिका के मुताबिक, हैदराबाद निवासी सुरेश पाल गुडू 'हॉर्स पावर लीग' के सूत्रधार हैं। उन्होंने हैदराबाद रेस क्लब में दो घोड़ों की रेस करवाकर 'ट्रोपंग करेठस्ता' नामक ऐप के जरिए फिलीपींस में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करवाकर सट्टा लगवाया था। फिलीपींस सरकार की शिकायत पर केंद्र सरकार ने इसे बंद करवाया था। सुरेश पाल के पास 150 से अधिक घोड़े थे, लेकिन चार महीने पहले उन्होंने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। भोजन-पानी न मिलने से हैदराबाद में ही करीब 90 घोड़ों की तड़पकर मौत हो गई। आरोप है कि साक्ष्य छुपाने के लिए केयरटेकर सचिन तिवारी ने 29 अप्रैल से 3 मई 2025 के बीच 57 घोड़ों को चोरी-छिपे जबलपुर लाकर पनागर के रैपुरा स्थित फार्म हाउस में रख दिया।

केयरटेकर के बयानों में भारी विरोधाभास

केयरटेकर सचिन तिवारी ने पहले कोर्ट में हलफनामा दिया था कि जबलपुर लाए गए 57 घोड़ों में से 19 की मौत हो चुकी है, 22 को उसने बेच दिया है और 3 नए घोड़े खरीदे हैं, यानी उसके पास 19 घोड़े सुरक्षित हैं। लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में केयरटेकर के वकील ने दावा किया कि अब सभी घोड़े बेच दिए गए हैं। इसी विरोधाभास के बाद कोर्ट ने ऑन-ग्राउंड जांच के आदेश जारी किए। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसल्वा और अधिवक्ता सोमेश अवस्थी ने पैरवी की।

भोजशाला से 2 किमी दूर चालीस-पीर परिसर में नमाज की अनुमति

फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज, सदर बोले-इतनी दूर व्यवस्था करना गलत

भोपाल। धार के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आज जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। इसमें प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए स्थान और समय तय कर दिया। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के विपरीत बताते हुए यहां नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल, जिला प्रशासन ने मालीवाड़ा स्थित 'चालीस पीर परिसर' को जुमे की नमाज के लिए तय किया है। इसके तहत मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यहां नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है।

मुस्लिम समाज की आपत्तिः 2 किमी दूर व्यवस्था करना गलत- मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा- जिस स्थान (भोजशाला) को लेकर कोर्ट में मुख्य विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उससे करीब 2 किलोमीटर दूर नमाज की व्यवस्था की है, जो न्यायसंगत नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर यह फैसला लिया है। इस पर मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि जब पहले भोजशाला परिसर में नमाज होती थी, तब भी शांति बनी रहती थी और नमाज बंद होने के बाद भी कभी कोई समस्या नहीं हुई। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक बैठक के तौर-तरीकों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सदर अब्दुल समद के मुताबिक, बैठक के नाम पर समाज के वरिष्ठ लोगों को 3 घंटे तक बैठाकर रखा गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए हमें विवादित स्थल से दूर जगह थमा दी गई। फैसले को चुनौती देंगे- मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला से बिलकुल सटे (पास के) किसी खाली स्थान पर व्यवस्था करने को कहा था।

बसंत पंचमी वाली जगह पर भी था विवाद

सदर ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इससे पहले 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर प्रशासन ने जिस जगह पर डमी नमाज कराई थी, वह दरअसल कब्रिस्तान की जमीन है। उस समय भी मुस्लिम समाज ने इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि कब्रिस्तान में जुमे की नमाज अदा नहीं की जाती। यह पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूती से रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने आदेश का अध्ययन कर यह वैकल्पिक व्यवस्था बनाई थी, लेकिन मुस्लिम समाज द्वारा इसका बहिष्कार करने और कानूनी लड़ाई जारी रखने के एलान के बाद धार में इस मामले को लेकर सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के टीम लीडर हरिशंकर जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और सनातनी योद्धा अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन के साथ अधिवक्ता विनय जोशी के नेतृत्व में 2 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका क्रमांक 10497/2022 दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री, आशीष गोयल, आशीष जनक, मोहित गर्ग और सुनील सारस्वत को 15 मई 2026 को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर 14 जुलाई को सुनवाई हुई।

सिंघार का आरोप-डैम बनाने वाली कंपनी ने 60 करोड़ चंदा दिया ; भाजपा ऑफिस बना रही

केन-बेतवा में आदिवासियों की जगह मुस्लिम को मिला मुआवजा

भोपाल। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को 44 हजार करोड़ रुपए की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। सिंघार ने दावा किया कि आदिवासी गांव में एक ऐसे मुस्लिम परिवार के खाते में भी मुआवजा पहुंचा, जो वहां रहता ही नहीं था। उन्होंने जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए और छतरपुर कलेक्टर पर जांच दबाने का आरोप लगाया। भोपाल में सिंघार ने कहा कि परियोजना का निर्माण कर रही नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी से भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसीलिए सरकार कंपनी के हित में काम कर रही है और प्रभावित आदिवासियों व किसानों की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और सोशल ऑडिट की मांग की।

80 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं से मारपीट की- सिंघार ने कहा- 14 जुलाई को मैंने पन्ना और छतरपुर के प्रभावित गांवों का दौरा किया। कूपी गांव में वे करीब पांच से सात घंटे विस्थापित परिवारों के बीच रहा। आंदोलन कर रहे आदिवासियों और किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 80 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट की गई। कई महिलाओं ने उन्हें पुलिस कार्रवाई की

आपबीती सुनाई। सिंघार ने सवाल उठाया कि सरकार कंपनी के लिए आदिवासियों और किसानों पर इतनी सख्ती क्यों कर रही है।

कानून के अनुसार ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं ली- नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, वहां कानून के अनुसार ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं ली गई। सिंघार का दावा है कि कई गांवों में ग्राम सभाएं हुई ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में उनकी कार्यवाही दर्ज कर दी गई। एक ग्राम पंचायत में सरपंच की जगह दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर कर दिए गए। सिंघार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया कानून के खिलाफ हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए।

1980 में गांव छोड़ गया था मुस्लिम परिवार, खाते में पैसा गया- सिंघार ने कहा- खरिहानी गांव में 11 करोड़ रुपए का मुआवजा स्वीकृत हुआ। इसमें से आठ करोड़ ऐसे व्यक्तियों को दे दिए गए जिन्होंने 1980-1990 में गांव छोड़ दिया। इस आदिवासी गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता फिर यह कहां से कैसे आ गए और उनके खाते में कैसे पैसा चला गया। छतरपुर कलेक्टर क्यों जांच दबाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या भाजपा के नेताओं का भ्रष्टाचार है। स्थानीय विधायक की भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं।

'दूसरे के नाम चढ़ा दी जमीन, मुआवजा भी मिल गया'- सिंघार ने सुखवा गांव की एक बुजुर्ग आदिवासी महिला का मामला उठाते हुए कहा कि उसकी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई। मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद मुआवजा दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बताए, ऐसी महिला को अब न्याय कैसे मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर 20 से 30 हजार रुपए प्रति व्यक्ति तक वसूले।

उज्जैन महाकुंभ के लिए एमपी पुलिस का मास्टर प्लान

लाठी-डंडे से नहीं,एआई और भीड़ की साइकोलॉजी से होगा क्राउड मैनेजमेंट

भोपाल। साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी से एक बेहद अनोखा और हाई-टेक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बार सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस पुराने और पारंपरिक तौर-तरीकों को छोड़ रही है। नए प्लान के मुताबिक, उज्जैन के राम घाट पर पहले श्रद्धालु के पहुंचने से बहुत पहले ही वहां तैनात होने वाले पुलिस अफसर वहां की एक-एक गली से वाकिफ हो चुके होंगे। वे चोक पॉइंट्स (जहां भीड़ फंसती है) का अध्ययन कर चुके होंगे, रेस्क्यू रूट्स को रट चुके होंगे और हर आरती के बाद भीड़ के उतार-चढ़ाव के पैटर्न को समझ चुके होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और क्राउड साइकोलॉजी का मेल

एमपी पुलिस इस बार सामान्य ब्रीफिंग के बजाय लोकेशन-स्पेसिफिक ट्रेनिंग, बिहेवियरल साइंस और एआई-असिस्टेड (AI) क्राउड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने जा रही है। अधिकारियों को ठीक उसी घाट, मंदिर, रास्ते या सेक्टर के लिए ऑन-ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां उनकी ड्यूटी लगाई जानी है। इसके साथ ही, भीड़ की मानसिकता को समझने के लिए 'क्राउड साइकोलॉजी' और संभावित जाम का पहले से अंदाजा लगाने के लिए 'एआई-बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स' का सहारा लिया जाएगा, जिससे किसी भी हादसे को होने से पहले ही रोका जा सके।

संवेदनशील इलाकों को ऑपरेशनल जोन में बांटा

उज्जैन जोन के एडीजी राकेश गुप्ता ने इस नई रणनीति की पुष्टि करते हुए बताया, 'यह रणनीति इस सिद्धांत पर तैयार की गई है कि अधिकारियों को श्रद्धालुओं के आने से बहुत पहले ही अपने तैनाती क्षेत्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम सिंहस्थ को एक सामान्य पुलिसिंग एक्सरसाइज के रूप में देखने के बजाय संवेदनशील स्थानों को छोटे-छोटे 'ऑपरेशनल जोन' में बांट रहे हैं। यहां तैनात होने वाले अफसरों को उस इलाके के भूगोल और भीड़ के मिजाज के हिसाब से खास ट्रेनिंग दी जाएगी।' उन्होंने साफ किया कि यह ट्रेनिंग कानून-व्यवस्था संभालने के पारंपरिक तरीकों से काफी आगे की होगी।